www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 25 अंक : 12 | गोरखपुर, 14 सितम्बर 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

▸ डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी

'भूपेन हजारिका का संगीत एक भारत-श्रेष्ठ भारत की पहचान'

गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल हुए। मोदी ने डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेते हुए उनके सम्मान में 'स्मारक सिक्का और डाक टिकट' जारी किया। वहीं, अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि आज का दिन अद्भुत है और ये पल अनमोल हैं। जो दृश्य यहां मैंने देखा, जो उत्साह और तालमेल मुझे दिखा, भूपेन संगीत की जो ली दिखी, अगर मैं भूपेन दा के शब्दों में ही कहूं, तो मन में बार-बार आ रहा था ' समय ओ धीरे चलो, समय ओ धीरे चलो।' नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी

▸ भूपेन हजारिका सम्मान में पीएम मोदी ने जारी किया 'स्मारक सिक्का और डाक टिकट'

कुछ दिन पूर्व ही 8 सितंबर को भूपेन हजारिका जी का जन्मदिवस बीता है। उस दिन मैंने भूपेन दा को समर्पित एक लेख में अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। मेरा सौभाग्य है कि उनके जन्मशताब्दी वर्ष के इस आयोजन में मुझे हिस्सा लेने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि भूपेन दा ने ऐसी अमर रचनाएं रचीं। जो अपने स्वरों से भारत को जोड़ती रहीं। जो भारत की पीढ़ियों को झकझोरती रहीं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बहुत गर्व से भूपेन दा के जन्मशताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट कर रही है। हम भूपेन हजारिका जी के गीतों को, उनके संदेशों को और उनकी जीवनयात्रा को घर-घर ले जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका जी ने जीवन पर्यंत संगीत की सेवा की। संगीत जब साधना बनता है, तो वो हमारी आत्मा को छूता है और संगीत जब संकल्प बनता है, तो वो समाज को नई दिशा दिखाने का माध्यम बन जाता है। भूपेन दा का संगीत इसलिए ही इतना विशेष था। उन्होंने जिन आदर्शों को जिया, जो अनुभव किया, वही अपने गीतों में भी गाया। हम उनके गीतों में मां भारती के लिए इतना प्रेम इसलिए देखते हैं, क्योंकि वो 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना

प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका जी ने जीवन पर्यंत संगीत की सेवा की। संगीत जब साधना बनता है, तो वो हमारी आत्मा को छूता है और संगीत जब संकल्प बनता है, तो वो समाज को नई दिशा दिखाने का माध्यम बन जाता है।

को जीते थे। भूपेन हजारिका का संगीत ह्यएक भारत श्रेष्ठ भारतह्ल की अवधारणा को समाहित करता है; वह भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में रचे-बसे थे।

उन्होंने कहा कि भूपेन दा भारत की एकता और अखंडता के महान नायक थे। दशकों पहले, जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था। तब भूपेन दा उस मुश्किल समय में भी भारत की एकता को ही आवाज देते रहे। मोदी ने कहा कि जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो लोगों को अक्सर रेल, रोड या एयर कनेक्टिविटी की याद आती है। लेकिन, देश की एकता के लिए एक और कनेक्टिविटी की जरूरत है, वो है कल्चरल कनेक्टिविटी। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में देश ने नार्थ ईस्ट के विकास के साथ साथ कल्चरल कनेक्टिविटी को भी बड़ी अहमियत दी है। ये एक अभियान है, जो अनवरत जारी है।

नेपाल में राजनीतिक अनिश्चितता पर लगा विराम

नेपाल को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की

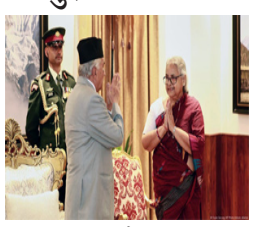

काठमांडू। 73 वर्षीया कार्की इससे पहले नेपाल की मुख्य न्यायधीश रह चुकी हैं। अब वो देश की अंतरिम प्रधानमंत्री के ऊपर व्यवस्था को बहाल करने और प्रदर्शनकारियों की मांग के मुताबिक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को संभव बनाने की जिम्मेदारी है पिछले दिनों भारी उथल-पुथल से गुजरे नेपाल में अब उन्हें सरकार बनाकर फिर से काम करने की स्थितियां पैदा करनी हैं। इसके साथ ही नेपाल में धीरे-धीरे सामान्य जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। सेना ने भी शुक्रवार को कर्फ्यू में ढील दे दी। देश में हफ्ते की शुरूआत से ही कर्फ्यू लगा हुआ था. सोमवार को सोशल मीडिया पर लगे बैन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते स्थिति विस्फोटक हो गई और प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन और बहुत सारी सरकारी इमारतों में आग लगा दी. इन हालात में केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। इन हिंसक प्रदर्शनों में 50 से ज्यादा लोगों की जान भी गई थी।

5 मार्च, 2026 को होंगे अगले चुनाव

मौजूदा संसद को भंग कर दिया गया है और अगले चुनावों के लिए 5 मार्च, 2026 की तारीख तय की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशीला कार्की को यह पद संभालने के लिए नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडल ने राजी किया। उनके सात जेनजी के प्रतिनिधि भी इस बातचीत में शामिल थे. नेपाल के युवा विरोध आंदोलन को जेनजी आंदोलन नाम दिया गया है। अपनी आजाद सोच के लिए मशहूर सुशीला कार्की जब पद संभालने के लिए राजी हो गईं, तब उनकी नियुक्ति की घोषणा की गई। नेपाल के बिल्कुल युवा समूह, जिनके समूह को जेनजी कहा जा रहा है, उन्होंने डिस्कॉर्ड नाम की एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए कार्की के नाम की सहमति बनाई थी। अब इसी ऐप के सहारे वो सरकार के आगे के कदमों को लेकर बहस कर रहे हैं। लोग अब जल्द ही उपद्रव को भुला देना चाहते हैं। ऐसे में नई प्रधानमंत्री का समाज के ज्यादातर वर्गों ने स्वागत किया है।

कार्की से उम्मीदें-ज्यादातर नेपाली लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की की नियुक्ति का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि यह एक सांकेतिक बदलाव है और इसमें स्थितियां बदलने का वादा भी छिपा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता 51 साल के सूरज भट्टाराई ने कहा, नेपाल को पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई है। हम सोचते हैं कि प्रधानमंत्री, जो हमारी पूर्व मुख्य न्यायधीश हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल की लड़ाई का नेतृत्व करेंगी और सुशासन को बढ़ावा देंगी। करीब दशक भर चले गृहयुद्ध और साल 2008 में देश से राजशाही के अंत के बाद से इस हफ्ते देश में सबसे बड़े हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद बुधवार से नेपाल में हर जगह पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया गया था। बहुत से लोगों को उम्मीद है कि कार्की नए नेपाल के उनके सपने को पूरा करेंगी।

मुख्यमंत्री ने हिन्दी दिवस और जीवित्पुत्रिका व्रत की दी शुभकामनाएं

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिन्दी दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत विविधताओं का देश है, जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिन्दी देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिन्दी भाषा देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। राष्ट्र को एकजुट रखने में हिन्दी का बहुत बड़ा योगदान है। हिन्दी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान तथा जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने राजभाषा हिन्दी के चतुर्दिक विकास की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में राजभाषा के रूप में हिन्दी सरकारी कामकाज की भाषा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने कामकाज में हिन्दी को ही माध्यम के रूप में अपनाएं तथा गर्व एवं सम्मान के साथ हिन्दी सीखें, समझें एवं प्रयोग में लायें। नीतीश कुमार ने जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) व्रत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ यह व्रत करती हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की है।

ममता ने सुशीला कार्की को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सुशीला कार्की को बधाई दी। नेपाल की पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की शुक्रवार रात अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं। इसके साथ ही, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद देशव्यापी आंदोलन के कारण के पी शर्मा ओली सरकार के इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने के बाद कई दिन से जारी राजनीतिक अनिश्चितता का अंत हो गया। बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच ह्यएक्सह्ल पर लिखा, ह्यह्यमैं माननीय श्रीमती सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं नेपाल से लगती हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। हम पड़ोसी देशों के रूप में मित्रता एवं सहयोग के गहरे संबंधों को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं ह्लह्ल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के तीन दिन बाद शुक्रवार शाम 73 वर्षीय कार्की को पद की शपथ दिलाई।

काठमांडूः नेपाल में तीन दिनों के राजनीतिक संकट के बाद शुक्रवार को देश का नया मुखिया मिल गया। देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही नेपाल की प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी नोटिस के अनुसार, संसद का निचला सदन 12 सितम्बर 2025 की रात 11 बजे से भंग हो गया है।

पुराने और अनुपयोगी वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम

▸ पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट

पटना। बिहार सरकार ने पुराने और अनुपयोगी वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने 15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों के मालिकों को टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही वाणिज्यिक वाहनों पर भी 50 प्रतिशत टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है।

राज्य सरकार पहले से ही स्क्रैपिंग कराने वाले वाहन स्वामियों को कई रियायतें दे रही है। स्क्रैपिंग के बाद प्राप्त प्रमाण पत्र, सीओडी के आधार पर नए वाहनों के पंजीकरण और बकाया टैक्स में वाहन मालिकों को एकमुश्त छूट दिया जा रहा है। इसके साथ पुराने वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों और अर्थदंड में एकमुश्त छूट देने का प्रावधान है। गैर परिवहन और परिवहन वाहन के देनदारियों में 90 प्रतिशत और अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग के लिए वाहन स्वामियों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद आरवीएसएफ सेंटर वाहन को खरीदकर स्क्रैप करेंगे। बिहार में इसके लिए दो स्क्रैपिंग सेंटर उपलब्ध हैं– पटना में निलियम स्क्रैपिंग सेंटर और वैशाली में एसके इंटरप्राइजेज।

▸ मुरैना में सुकन्या समृद्धि योजना के विस्तार की घोषणा

बेटियाँ परिवार की जिम्मेदारी नहीं, पूरे समाज की पहचान हैं: सिंधिया

मुरैना/ग्वालियर/नई दिल्ली। केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शनिवार को मुरैना में सुकन्या समृद्धि योजना के विस्तार की घोषणा और प्रधान डाकघर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। केन्द्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बेटियां हमारे समाज को गढ़ने का कार्य करती हैं और सुकन्या समृद्धि योजना केवल बैंक खाता नहीं, बल्कि यह माता का आत्मविश्वास, पिता का गर्व और पूरे समाज का भरोसा है। साथ ही उन्होंने बताया कि नवलोकार्पित पासपोर्ट सेवा केन्द्र से क्षेत्र के युवाओं और सभी नागरिकों को सुविधा और सहूलियत मिलेगी।

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने मुरैना में सुकन्या समृद्धि योजना का विस्तार किया और बताया कि अन्य जिलों की तरह अब मुरैना की बेटियां भी अपने सपनों की उड़ान भरेंगी। विदित रहे कि अब तक अशोकनगर की 929, शिवपुरी की 818 और गुना की 733 बेटियाँ, यानी लगभग 2500 परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। सिंधिया ने याद दिलाया कि पिछली बार उन्होंने स्वयं बेटियों के खाते खुलवाए थे और निजी सहयोग भी किया था। इस अवसर पर उन्होंने दोहराया कि 1 मई 2026 तक जो भी बेटियाँ इस योजना से जुड़ेंगी, उनके खातों में उनका व्यक्तिगत सहयोग रहेगा। इस सहयोग को सिंधिया ने केवल आर्थिक नहीं, बल्कि क्षेत्र की बेटियों के सपनों को उड़ान का उत्प्रेरक बताया। इस अवसर पर सिंधिया ने बेटियों के माता पिता से कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलकर वे सिर्फ बैंक से नहीं जुड़े हैं बल्कि उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य पर भरोसा जताया है। केन्द्रीय मंत्री ने सभी माताओं एवं पिताओं से इस भरोसे को हर महीने की बचत और हर रोज के सहयोग से और मजबूत करने का आह्वान किया।

मुरैना में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए सिंधिया ने कहा कि अब जिले के नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए ग्वालियर, गुना या भोपाल नहीं जाना पड़ेगा। इस केंद्र से मुरैना और श्योपुर जिले के साथ-साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। यह केंद्र प्रतिदिन 40 अतिरिक्त अपॉइंटमेंट स्लॉट उपलब्ध कराएगा। मंत्री सिंधिया ने कहा कि यह भवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सुविधा और सशक्तिकरण का प्रतीक बनेगा।

विदित रहे कि बेटियों के हाथ में कलम देकर समाज में बदलाव लाने की सिंधिया परिवार की परंपरा रही है। अपने संबोधन में सिंधिया ने अपनी आजी अम्मा राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी को याद करते हुए बताया कि वे कहा करती थी कि जो हाथ शिशु के पालने को झुला सकते हैं, वे हाथ विश्व पर भी राज कर सकते हैं। इसी परंपरा और प्रण का निर्वहन करते हुए सिंधिया ने क्षेत्र की हर बेटी के उत्थान और सपने पूरे करने का संबल देने का संकल्प लिया है।

सिंधिया ने चंबल के सर्वांगीण विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए पानी के संकट को दूर करने का भरोसा दिलाया। साथ ही अपने पूज्य पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करते हुए श्योपुर से कोटा तक ट्रेन सेवा को साकार करने की प्रतिबद्धता जताई।

सिंधिया ने यह भी कहा कि मुरैना हाईवे के 88 किलोमीटर के कार्य पूर्ण होने के बाद मुरैना से दिल्ली महज ढाई घंटे से भी कम समय में पहुंचा जा सकेगा, जिससे विकास और रोजगार की नई संभावनाएँ खुलेंगी। अपने उद्बोधन के अंत में भावुक होकर सिंधिया ने कहा मेरे शरीर में जितनी भी ऊर्जा है, उसका एक-एक कण चंबल, ग्वालियर और मालवा की धरती को समर्पित है।

सिंधिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश और देश सुविधा, सशक्तिकरण और सहूलियत के संगम-पथ पर अग्रसर है। उन्होंने सभी नागरिकों को पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना पर बधाई दी और अभिभावकों से सुकन्या समृद्धि योजना से अधिक से अधिक जुड़ने का आह्वान किया।

ज्योतिरादित्य सिंधिया का हुआ स्वागत

ग्वालियर/भोपाल। केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के शनिवार को मुरैना आगमन पर हजारों नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व स्वागत किया। जगह-जगह पुष्पवर्षा, ढोल-नगाड़ों की थाप और गगनभेदी नारों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। सिंधिया ने जनता के इस अपार स्नेह और आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी शक्ति और सेवा का संकल्प बताते हुए कहा कि यह प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद ही मेरी असली पूंजी है।

सबसे बड़ी चुनौती है सामुदायिक बंधनों का क्षरण। गाँवों में जहाँ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच गहरे संबंध होते हैं, वहीं शहरों में रहने वाले लोग अक्सर अनजानेपन और दूरी का अनुभव करते हैं। गेटेड सोसाइटी और उच्च-आय वर्गीय कॉलोनियों ने सामाजिक जीवन को खंडित कर दिया है। लोग अपने छोटे-से घेरे में सिमट जाते हैं और अन्य के प्रति अविश्वास पनपने लगता है। यह प्रवृत्ति समाज में सामूहिक विश्वास और सहयोग की भावना को कमजोर करती है। शहरी जीवन का दूसरा बड़ा संकट है अकेलापन। भीड़भाड़ और व्यस्तता के बावजूद लोग व्यक्तिगत रूप से अलग-थलग पड़ जाते हैं।

तरक़्क़ी के शहर, अकेलेपन के घर

महानगरों में लाखों लोग रहते हैं, परंतु अधिकांश अपने पड़ोसियों को भी नहीं पहचानते। एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत शहरी भारतीयों ने स्वीकार किया कि वे खुद को अकेला महसूस करते हैं। यह आँकड़ा दिखाता है कि आधुनिक शहरी जीवन ने भले ही हमें भौतिक सुविधाएँ दी हों, परंतु भावनात्मक और सामाजिक रूप से हमें कमजोर किया है। तकनीक ने भी इस अकेलेपन को बढ़ाया है। स्मार्ट-फोन और सोशल मीडिया पर निर्भरता ने वास्तविक मानवीय बातचीत को सीमित कर दिया है। मेट्रो या बस में सफर करते हुए अक्सर लोग एक-दूसरे से संवाद नहीं करते, बल्कि मोबाइल स्क्रीन में डूबे रहते हैं।

शहरीकरण ने भारत के सामाजिक जीवन और मानवीय संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है। यह केवल आर्थिक प्रगति का साधन नहीं बल्कि एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन भी है जिसने हमारे पारंपरिक रिश्तों, विश्वास और आपसी सहयोग की प्रकृति को बदल दिया है।

शहरी जीवन की रफ्तार, अवसरों की विविधता और सेवाओं तक आसान पहुँच ने निश्चित ही नागरिकों को नए विकल्प दिए हैं, परंतु इसके साथ ही यह प्रक्रिया मानवीय संवेदनाओं और सामुदायिक रिश्तों को भी चुनौती देती रही है। शहरों के विस्तार ने लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अवसरों के करीब लाया। पहले जहाँ ग्रामीण भारत में इन सुविधाओं तक पहुँच कठिन थी, वहीं शहरी क्षेत्रों ने इन्हें आसान बनाया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे महानगरों में विश्वस्तरीय अस्पताल, विश्वविद्यालय और सांस्कृतिक केंद्र मौजूद हैं।

यह स्थान केवल सेवाएँ ही उपलब्ध नहीं कराते, बल्कि ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान के मंच भी बनते हैं। इसी वजह से शहरी जीवन को आधुनिक भारत का इंजन कहा जाता है। यहाँ के निवासी विभिन्न भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिससे विविधता का अनुभव होता है और सहिष्णुता की भावना विकसित होती है।

साथ ही, शहरी जीवन में सांस्कृतिक समृद्धि और नागरिक चेतना भी प्रबल होती है। कला दीघाएँ, पुस्तकालय, रंगमंच, साहित्यिक सभाएँ और जनआंदोलन जैसी गतिविधियाँ शहरों की पहचान रही हैं। चाहे वह कोलकाता की अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स हो या दिल्ली का इंडिया हैबिटेट सेंटर—ये स्थान सामूहिक संवाद और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, बेंगलुरु जैसे शहरों में आईटी उद्योग और स्टार्टअप संस्कृति ने पेशेवर सहयोग और नेटवर्किंग की नई संभावनाएँ खोली हैं। नागरिक स्वयं भी संगठित होकर अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए आवाज उठाते हैं। गुरुग्राम की आवासीय कल्याण समितियों द्वारा कचरा प्रबंधन और जलभराव के खिलाफ अभियान इसका उदाहरण हैं।

लेकिन इन सब सकारात्मक पहलुओं के बीच शहरीकरण का एक दूसरा चेहरा भी है, जो कहीं अधिक गहन सामाजिक संकट की ओर इशारा करता है। सबसे बड़ी चुनौती है सामुदायिक बंधनों का क्षरण। गाँवों में जहाँ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच गहरे संबंध होते हैं, वहीं शहरों में रहने वाले लोग अक्सर अनजानेपन और दूरी का अनुभव करते हैं। गेटेड सोसाइटी और उच्च-आय वर्गीय कॉलोनियों ने सामाजिक जीवन को खंडित कर दिया है। लोग अपने छोटे-से घेरे में सिमट जाते हैं और ₹अन्य₹ के प्रति अविश्वास पनपने लगता है। यह प्रवृत्ति समाज में सामूहिक विश्वास और सहयोग की भावना को कमजोर करती है।

शहरी जीवन का दूसरा बड़ा संकट है अकेलापन। भीड़भाड़ और व्यस्तता के बावजूद लोग व्यक्तिगत रूप से अलग-थलग पड़ जाते हैं। महानगरों में लाखों लोग रहते हैं, परंतु अधिकांश अपने पड़ोसियों को भी नहीं पहचानते।

एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत शहरी भारतीयों ने स्वीकार किया कि वे खुद को अकेला महसूस करते हैं। यह आँकड़ा दिखाता है कि आधुनिक शहरी जीवन ने भले ही हमें भौतिक सुविधाएँ दी हों, परंतु भावनात्मक और सामाजिक रूप से हमें कमजोर किया है।

तकनीक ने भी इस अकेलेपन को बढ़ाया है। स्मार्ट-फोन और सोशल मीडिया पर निर्भरता ने वास्तविक मानवीय बातचीत को सीमित कर दिया है। मेट्रो या बस में सफर करते हुए अक्सर लोग एक-दूसरे से संवाद नहीं करते, बल्कि मोबाइल स्क्रीन में डूबे रहते हैं। यह प्रवृत्ति समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल की उस धारणा को सही साबित करती है जिसमें उन्होंने आधुनिक शहरों को ₹भीड़ में अकेलेपन₹ का प्रतीक कहा था।

साथ ही, शहरी जीवन की भीड़-भाड़ और संसाधनों की कमी ने तनाव और संघर्ष को भी जन्म दिया है। पानी, बिजली, यातायात और पार्किंग जैसे मुद्दों पर झगड़े आम हो गए हैं। दिल्ली जैसे शहरों में पार्किंग विवाद कई बार हिंसा तक पहुँच जाते हैं। वाहन प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाएँ भी नागरिक जीवन की असुरक्षा को बढ़ाती हैं। पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित स्थान कम होते जा रहे हैं, जिससे साझा सार्वजनिक जीवन घटता जा रहा है। यह कमी सामाजिक पूँजी पर सीधा आघात करती है, क्योंकि खुले और सुरक्षित सार्वजनिक स्थल ही लोगों के बीच संवाद और सहयोग को जन्म देते हैं।

इस प्रकार, शहरीकरण ने भारत के सामाजिक पूँजी पर दोतरफा असर डाला है। एक ओर इसने शिक्षा, स्वास्थ्य, विविधता और सांस्कृतिक उन्नति के अवसर दिए, तो दूसरी ओर इसने रिश्तों को सतही, अस्थिर और अविश्वासी बना दिया। आर्थिक विकास की गति में हमने भावनात्मक और सामुदायिक जीवन को पीछे छोड़ दिया।

आवश्यक है कि शहरी नियोजन केवल भौतिक ढाँचे तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें मानवीय संबंधों की गरिमा और सामुदायिक जीवन की बहाली को भी स्थान मिले। हमें ऐसे सार्वजनिक स्थल चाहिए जहाँ लोग सहजता से मिल सकें और संवाद कर सकें। आवासीय कल्याण समितियों को केवल प्रशासनिक इकाई न मानकर सामाजिक मेलजोल और सामुदायिक उत्सवों का मंच बनाया जाए। शहरों में त्योहारों, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोग एक-दूसरे के करीब आ सकें। साथ ही, सस्ते और समावेशी आवास की नीतियाँ तैयार हों, जिससे वर्ग आधारित विभाजन कम हो सके।

भारत का भविष्य निस्संदेह शहरी होगा, परंतु यह भविष्य तभी स्थायी और समृद्ध हो सकता है जब शहरीकरण केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक पूँजी का भी संवाहक बने।

हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास की दौड़ में रिश्तों का ताना-बाना न टूटे। शहर तभी सच्चे अर्थों में प्रगतिशील बनेंगे जब वे न केवल समृद्धि और अवसर देंगे, बल्कि विश्वास, सहयोग और सामूहिक कल्याण की भावना को भी जीवित रखेंगे।

प्रियंका सौरभ

थारू विकास भवन में चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम

खटीमा। केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल की ओर से थारू विकास भवन में चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम के दूसरे दिन गत दिनों शुक्रवार को चलचित्र व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम लोगों को जागरूक किया गया। इसमें बताया गया कि भारत सरकार की ओर से 2018 से कुपोषण के खात्मे के लक्ष्य को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। बाल विकास अधिकारी नीरज भट्ट की देखरेख में जंक फूड से दूर रहने व पोषण मील की जानकारी दी गई। इस दौरान मेहंदी प्रतियोगिता, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थारू उत्थान समिति की ओर से रंगारंग कार्यक्रम व पोषण आहार की प्रदर्शनी भी प्रस्तुत की गई। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण भी किया गया। वहां पर मुख्य अतिथि नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा, नगर पालिकाध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित पांडेय, समेत अनेक लोगउपस्थित थे।

हिंदी की चुनौतियां और समाधान शीर्षक पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन

पिथौरागढ़। गंगोत्री गर्ब्याल जीजीआईसी में हिंदी दिवस पर स्कूल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत हिंदी की चुनौतियां और समाधान शीर्षक पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरूआत हिंदी के महत्व और उसके गौरवशाली इतिहास की जानकारी साझा करने के साथ हुई। जीजीआईसी से तस्कीन, खुशी, द स्कॉलर्स एकेडमी स्कूल से तेजस्विनी, माही ने पक्ष जबकि साक्षी, कंचन, अनुष्का, नीरा ने विपक्ष में बेबाकी से अपने विचार व्यक्त किए। पक्ष ने हिंदी का स्वर्णिम इतिहास व उसकी महत्ता को दशार्या और विपक्ष में अन्य भाषाओं की महत्ता और उनको एक दर्जे पर रखने पर जोर दिया गया। स्कॉलर्स एकेडमी की अनुष्का और जीजीआईसी की तस्कीन फातिमा को बेस्ट स्पीच अवॉर्ड से सम्मानित किया और सभी प्रतिभागियों को उपहार बांटे गए। जीजीआईसी की प्रधानाचार्या हंसा धामी ने स्कूल एक्सचेंज कार्यक्रम को एक सराहनीय पहल बताया। इस दौरान शहजादी गौसिया, गीता तिवारी आदि मौजूद रहीं।

सुरसागर संगीत महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न

जोधपुर। सुरसागर संगीत महाविद्यालय में आयोजित कवि सम्मेलन में आमंत्रित कवियों ने अपनी शानदार प्रस्तुति देकर छात्रों और दर्शकों को आनंदित किया। सुरसागर संगीत महाविद्यालय में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आज आयोजित हुए जिसमें, हवन, पूजा, आरती आदि है ।कवि सम्मेलन भी इस कार्यक्रम का एक हिसा था। आज के आमंत्रित कवियों में सीमा रंगा इन्द्रा,चम्पा पाण्डेय, मनी अभय मिश्रा,विकास मिश्र, डॉ नाथू लाल,समरजीत सिंह,शुभम श्याम और रमेश गंगेले शामिल थे ।कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश गंगेले जी ने की और कार्यक्रम का संचालन विकास मिश्र ने किया ।कार्यक्रम का आगाज शुभम श्याम ने अपने शानदार गीतों से किया,तत्पश्चात समरजीत ने अपने शेरों से सभी को बहुत प्रभावित किया ।चंपा पाण्डेय ने लाजबाव गीत पढ़ा,मनी अभय मिश्रा ने बेहतरीन गीत सुनाया जिसे सभी ने खूब सराहा। नाथूलाल ने बेहतरीन गजल सुनाई ।सीमा रंगा ने बेहतरीन छंद पढ़कर सभी को बहुत प्रभावित किया। दर्शकों ने उनके गीतों पर खूब तालिया बजाई ।विकास मिश्र ने बेहतरीन मुक्तक पढ़ा और अपने संचालन से सभी को प्रभावित किया ।सभी ने विकास मिश्र के संचालन की सराहना की। कार्यक्रम अध्यक्ष रमेश गंगेले ने बेहतरीन गीत पढ़ा और सभी को अपनी शुभकामनाएं दी ।सभी कवियों को तिलक लगाकर,माला पहनाकर शाल ओढ़ाकर महाविद्यालय की तरफ से सम्मानित किया गया ।कार्यक्रम के आयोजक एवं सुरसागर संगीत महाविद्यालय के सर्वेसर्वा अनिल गुप्ता ने मीडिया को बताया लगभग 21 वर्षों से ये महाविद्यालय चल रहा है। यहां के छात्र नवरात्रों,दीवाली गणेश पूजा के समय में अनेक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति देते है तो बहुत अच्छा लगता है ।इस कार्यक्रम में सुर सागर संगीत महाविद्यालय की प्राचार्या ,शिक्षिका,छात्र एवं छात्राएं भी मौजूद रही ।अंत में भंडारा का प्रसाद भी सभी ने ग्रहण किया। **प्रस्तुति सीमा रंगा इन्द्रा**

हरियाणा में डेंगू का प्रकोप तेज है, लेकिन नगर निकायों के पास फॉगिंग मशीनों की भारी कमी है। प्रदेश के 87 निकायों में केवल 426 मशीनें उपलब्ध हैं, जो आवश्यकतानुसार बेहद कम हैं। मशीनों की कमी के कारण न तो शहरों में और न ही ग्रामीण इलाकों में नियमित फॉगिंग अभियान चल पाए हैं। 1200 से अधिक गाँव जलभराव से जूझ रहे हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग और निकायों की लापरवाही से जनता पर बीमारी का संकट गहराता जा रहा है। ठोस कार्ययोजना और पर्याप्त संसाधन ही डेंगू से सुरक्षा का रास्ता हैं।

जनता बीमार, प्रशासन लाचार : डेंगू का वार

डेंगू का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। हर साल मानसून के बाद बरसात के दिनों में जब मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, तो डेंगू के मामले तेजी से सामने आने लगते हैं। बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द और प्लेटलेट्स की कमी से पीड़ित मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ने लगती है। सरकारें हर वर्ष दावा करती हैं कि मच्छरों की रोकथाम और फॉगिंग के इंतजाम पूरे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट होती है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट ने हरियाणा के स्वास्थ्य तंत्र और स्थानीय निकायों की तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। प्रदेश के 87 नगर निकायों में डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए मात्र 426 फॉगिंग मशीनें ही उपलब्ध हैं। यानी लगभग हर निकाय के हिस्से में औसतन पाँच मशीनें भी नहीं आतीं। जबकि स्थिति यह है कि एक मध्यम आकार के शहर में ही डेंगू पर काबू पाने के लिए 20ञ्च 25 मशीनें आवश्यक मानी जाती हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश के स्तर पर मशीनों की यह कमी सीधा संदेश देती है कि प्रशासनिक लापरवाही किस हद तक हावी है।

डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसका सीधा इलाज एंटीबायोटिक दवाइयों से संभव नहीं है। यह मच्छरों से फैलने वाला वायरल संक्रमण है और रोगी के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ही उपचार टिका होता है। अधिकतर मामलों में डेंगू का वायरस शरीर की प्लेटलेट्स तेजी से घटा देता है। समय पर इलाज न मिलने पर यह स्थिति जानलेवा हो सकती है। भारत में हर साल लाखों लोग डेंगू से प्रभावित होते हैं और हजारों मौतें भी होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी डेंगू को दुनिया के सबसे तेजी से फैलने वाले वायरल रोगों में गिनता है। इसलिए रोकथाम ही सबसे बड़ा हथियार है। मच्छरों को पनपने से रोकना, जलभराव हटाना और समय-समय पर फॉगिंग करना – यही डेंगू पर नियंत्रण के सबसे कारगर उपाय हैं। लेकिन जब यही इंतजाम कमजोर पड़ जाएं, तो बीमारी का फैलाव तेजी से होता है।

हरियाणा के नगर निकायों के पास फॉगिंग मशीनों की संख्या न सिर्फ कम है बल्कि जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनमें से कई पुराने और खराब हालत में हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति राज्य सरकार और निकायों की उदासीनता को उजागर करती है। फॉगिंग का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि यह मच्छरों के जीवन चक्र को तोड़ती है। मच्छर के अंडे से निकलने और उनके वयस्क होने की प्रक्रिया पर फॉगिंग सीधा असर डालती है। यदि यह नियमित अंतराल पर हो तो मच्छरों की संख्या तेजी से कम हो सकती है। लेकिन जब मशीनें ही उपलब्ध न हों, तो फॉगिंग का अभियान केवल कागजों में रह जाता है।

यह समस्या सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। प्रदेश के 1200 से अधिक गाँव जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। गाँवों में नालियों की सफाई और कचरे के निस्तारण की व्यवस्था कमजोर है। पंचायतों के पास न तो पर्याप्त बजट है और न ही तकनीकी संसाधन। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप और भी खतरनाक हो सकता है। सरकारी नीतियों में बार-बार शहरी क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएँ और रोकथाम अभियान बिल्कुल नाममात्र के रह जाते हैं। इस स्थिति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों पर आती है। हर साल डेंगू का मौसम आता है और हर बार प्रशासन अचानक हाथ-पैर मारता है। जबकि यह समस्या नई नहीं है। फॉगिंग मशीनें सालभर सक्रिय रहनी चाहिए और नियमित अंतराल पर उनका रखरखाव होना चाहिए। लेकिन निकायों के पास अक्सर यह तर्क होता है कि बजट की कमी है। सवाल यह उठता है कि जब स्वास्थ्य सेवाओं पर ही खर्च नहीं होगा तो विकास का दावा किस आधार पर किया जाएगा?

मशीनों की कमी और लापरवाही का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। हर साल हजारों परिवार डेंगू से प्रभावित होते हैं। एक बार किसी घर का सदस्य डेंगू से बीमार हो जाए तो उस परिवार पर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। अस्पतालों में भर्ती का खर्च, दवाइयों और प्लेटलेट्स की कमी का संकट, लंबे समय तक काम और पढ़ाई से दूरी, बीमारी का डर और असुरक्षा—ये सभी पहलू जनता को झकझोरते हैं। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके पास महंगे इलाज का साधन नहीं होता।

सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इस स्थिति से सबक लें। सबसे पहले फॉगिंग मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए और हर निकाय को पर्याप्त मशीनें दी जाएं। केवल आपातकालीन हालात में नहीं बल्कि पूरे वर्ष तय अंतराल पर फॉगिंग होनी चाहिए। पंचायतों को बजट और मशीनें उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरनाशी अभियान चलाना आवश्यक है। जनता को भी जागरूक किया जाए कि घरों में पानी जमा न होने दें, कूलर व टंकियों को ढककर रखें। अस्पतालों में डेंगू टेस्ट, दवाइयों और प्लेटलेट्स की पर्याप्त व्यवस्था समय रहते की जाए।

डेंगू हर साल एक बार नहीं बल्कि अब स्थायी खतरे के रूप में सामने आ चुका है। बदलते मौसम, बढ़ते शहरीकरण और जलभराव की समस्याओं ने इसकी जड़ें और गहरी कर दी हैं। ऐसे में केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। फॉगिंग मशीनों की कमी और प्रशासनिक उदासीनता न केवल लापरवाही है बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ भी है। सरकार को चाहिए कि इस समस्या को आपदा प्रबंधन की तरह प्राथमिकता दे और हर निकाय को संसाधन उपलब्ध कराए। जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझे और घर-आसपास पानी जमा न होने दे। प्रशासन और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। आज जरूरत है एक ठोस कार्ययोजना की, वरना डेंगू हर साल नए रूप में दस्तक देता रहेगा और स्वास्थ्य तंत्र की कमजोरियों को उजागर करता रहेगा।

डॉ. सत्यवान सौरभ

दून पुस्तकालय में वित्तीय साक्षरता सत्र का आयोजन

जीवन लक्ष्यों के लिए एक मजबूत आधार का निर्माण विषय पर वक्ताओं ने किया विचार विमर्श

देहरादून। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में गत बुधवार को एनएसई और सेबी की ओर से एक वित्तीय साक्षरता सत्र का आयोजन किया गया। इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की ओर से एक परिचयात्मक सत्र प्रस्तुत किया गया। सत्र का संचालन सेबी-प्रमाणित प्रतिभूति बाजार प्रशिक्षक डॉ. सुनील मदान ने किया। सत्र का विषय, जीवन लक्ष्यों के लिए एक मजबूत आधार का निर्माण था जिसमें डॉ. मदान ने युवाओं को वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। उन्होंने छह प्रमुख स्तंभों, जरूरतें बनाम चाहत, 50-30-20 नियम, निवेश के सिद्धांत, म्युचुअल फंड, धोखाधड़ी से बचाव पर चर्चा की। सत्र में डॉ. वाबी चौरसिया, विनोद सकलानी, सुंदर सिंह बिष्ट, शुभम ममगाई, अंकिता, जगदीश सिंह महर, राकेश कुमार, अवतार सिंह समेत छात्र, शिक्षक और अन्य लोग उपस्थित रहे।

हिमालयी चारागाहों और मानव जीव संघर्ष पर व्याख्यान का आयोजन

हिमालयी क्षेत्रों के चारागाहों का हो रहा क्षरण : डॉ. रावत

अल्मोड़ा। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल में बुधवार को हिमालयी चारागाहों और मानव जीव संघर्ष पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। डॉ. जीएस रावत ने पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के लिए एसओपी बनाने और सामुदायिक संस्थाओं को सशक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने हिमालयी क्षेत्रों में चारागाहों और मानव जीव संघर्ष की बारीकियों से अवगत कराया। कहा कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लद्दाख, चांगथांग, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और उत्तरी सिक्किम के रेंजलैंड की स्थिति के बारे में बताया। डॉ. जीएस रावत ने कहा कि विदेशी आक्रामक प्रजातियों ने हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण और दुर्लभ प्रजातियों को समाप्त या समाप्ति की कगार पर कर दिया है। इसके समाधान के लिए हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को एकजुट होकर आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिमालय के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है इसलिए हिमालय से जुड़े सभी हितधारकों को नीतिगत समाधान कर इन प्रजातियों के प्रबंधन की दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

पुस्तक मेलों में अब पहले जैसे भीड़ उमड़ती नहीं दिखती

विजय गर्ग

जीवन में परिवर्तन अच्छा लगता है, लेकिन परिवर्तन का तात्पर्य यह नहीं कि हम अपनी संस्कृति को ही दरकिनार कर दें। कुछ ऐसा ही हमारा पुस्तकों के प्रति लगाव को देखा जा रहा है। खासकर युवा पीढ़ी और पुस्तक संस्कृति के बीच दूरियां काफी चिंता का विषय बन गई है। आज के युवाओं के बीच पुस्तकों के प्रति लगाव कम होने का मुख्य कारण डिजिटल दुनिया है, जहां स्मार्टफोन या मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक क्लिक के साथ किसी को हर तरह की सामग्री मिल जाती है। मगर सब कुछ व्यापक उपलब्धता के बीच पुस्तकों की जगह दिनों-दिन सिकुड़ती जा रही है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पुस्तकों से युवा पीढ़ी का जुड़ाव कम होना न केवल युवा पीढ़ी के ज्ञान और रचनात्मकता को प्रभावित करती है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और साहित्य के संरक्षण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। समय रहते इस विषय पर गौर करना बेहद महत्त्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि डिजिटल मीडिया हमारे लिए बेहद अहम बनता जा रहा है, लेकिन किताबों से इसकी तुलना करना व्यर्थ है। एक पुस्तक हमारे दिमाग के विकास के लिए बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं, तो इससे हमारे दिमाग में एकाग्रता का विकास होता है और इस–के साथ ही हमारे ज्ञान की गहराई में इजाफा होता है।

आज की दौड़ती भागती जिंदगी में युवा पीढ़ी के पास इतना समय ही नहीं है कि वह अपने इतिहास और विचार-गहनता की सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए उन पर गहन अध्ययन को प्राथमिक और जरूरी माने।

पुस्तक मेलों की चमक यह बेवजह नहीं है कि पुस्तक मेलों में अब पहले जैसे भीड़ उमड़ती नहीं दिखती है। एक समय था, जब युवा पीढ़ी को इंतजार रहता था कि कब पुस्तक मेला लगे और वे अपनी पसंद की किताबें खरीद कर लाएं। अब तक किताबें ही मार्गदर्शन के साथ हमारा समय बिताने की साथी रही थीं। आज का युवा किताबों को ई-बुक पर पढ़ना चाहता है, ताकि आधुनिक होने का अहसास हो। मगर क्या हमें लगता है कि किताब को बिना स्पर्श किए वह अनुभूति हो सकती है जो हाथ में किताब लेकर पढ़ने में मिलती है ?

दरअसल, किताब वह अहसास है जो जानकारियों और जिज्ञासाओं से बांधे रखता है। आज युवाओं के बीच नकारात्मकता इस कदर घर करती जा रही है कि इसकी वजह से ध्यान सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रही। किताबें हम अक्सर उस समय पढ़ते हैं, जब हमें महसूस होता है कि खाली समय है या फिर अकेलापन महसूस हो रहा है। ऐसी स्थिति में किताबें किसी दोस्त की तरह काम करती हैं। उनको पढ़कर एक अलग-सी शांति मिलती है। जहां हम तनाव महसूस करते हैं, वहां किताबें हमारे अंदर से तनाव को निकालकर दिमाग में सकारात्मकता और जीवन जीने की इच्छा को भर देती हैं। एक समय था जब किसी जगह पुस्तकालय मिल जाता था तो एक उत्सुकता होती थी वहां बैठ कर किताबे पढ़ने की पुस्तकालयों में पुस्तकों का इतना अधिक संग्रह होता था कि हमारे अंदर उन्हें पढ़ने की भी अलग-सी ललक होती थी। वहां हमें अपनी संस्कृति और विरासत की झलक दिखाई देती थी। मगर आज युवा पीढ़ी के किताबों के प्रति अनदेखी करने वाले रवैए ने पुस्तकालयों को जैसे विलुप्त ही कर दिया है। आज के युवा इस कदर व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वे किताबों के लिए पुस्तकालय जैसी जगह पर जाएं।

बढ़ती होड़

मुश्किल यह है कि आज युवा पीढ़ी में एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा खड़ी हो गई है, जो उन्हें दिन-रात चैन से जीने नहीं देती है। खासकर माता-पिता की इच्छाएं युवाओं पर एक बोझ की तरह काम करने लगी हैं। उन्हें भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए शिक्षा में 'सबसे अव्वल' आने को अपना लक्ष्य बनाना है। इस क्रम में सिर पर पढ़ाई इस कदर हावी हो रही है कि युवाओं के पास समय की बेहद कमी होती जा रही है और वे अपने पाठ्यक्रम से अलग ज्ञान और सृजनात्मक साहित्य की पुस्तकें नहीं पढ़ पाते। जीवन में जो पुस्तकें हमें असल में वास्तविकता को दिखाती हैं, अगर उन्हें खरीदा भी जाता है तो अलमारी में सजा कर रखने के लिए।

यह एक विचित्र विडंबना है कि डिजिटल मंचों पर किसी भी चीज को खोज कर हमें विश्वास हो जाता है कि वह सही ही होगी, लेकिन इसके विपरित एक किताब को हम नहीं पढ़ना चाहते, जिसे किसी लेखक ने अपने अनुभवों से सींचा होगा, बड़ी मेहनत से लिखा होगा और उसमें वास्तविकता दर्ज होगी। क्या हमने कभी सोचा है कि हम गूगल में खोज कर जो चीजें हासिल करते हैं, उनकी विश्वसनीयता कितनी होती है ? हम इस ओर ज्यादा गौर नहीं करते है, क्योंकि हमें सिर्फ पकी पकाई सामग्री चाहिए होती है। यहां युवाओं को समझना होगा कि अगर उन्हें ज्ञान से लैस जागरूक नागरिक बनना है, तो जरूरी है कि वे पुस्तकों से दूरी न बनाएं। उनमें विषयों को खोजें। जो गुणवत्ता से लैस जानकारी पुस्तकों में मिलेगी, उसकी तुलना डिजिटल मंचों पर बिखरी हुई सामग्री में नहीं मिलेगी।

बुद्धिमत्ता का विकास

किताबें नियमित रूप से पढ़ने से याददाश्त में बढ़ोतरी होती है। साथ ही इससे तनाव से मुक्ति और स्फूर्ति भी मिलती है। अगर किताबों को ध्यान से पढ़ा जाए तो विषय की गहरी समझ पैदा होती है। साथ ही किताबें भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति विकसित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुस्तकें ज्ञान, कल्पना और रचनात्मकता का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। वे हमें विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के बारे में जानने में मदद करती हैं और हमें दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाती हैं। जीवन में बहुत से उतार-चढ़ाव को हम किताबों के जरिए भी जान पाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, अगर हम रात को सोने से पहले किताब पढ़ते हैं तो हमें बेहद सुकून भरी नींद आती है। पूरे दिन में पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है तो रात को सोते समय मोबाइल पर वक्त बिताने से अच्छा है कोई किताब पढ़ी जाए। जिस दिन हमने पुस्तक को अपनी धरोहर की तरह संभाल कर उसे पढ़ना शुरू कर दिया, तो जीवन के सारे अवसाद स्वयं ही खत्म होते दिखेंगे। अच्छी नींद के साथ सुबह मन खुशनुमा महसूस करेगा।

मलोट पंजाब

भारतीय ज्ञान परंपरा और वैश्विक नेतृत्व की अवधारणा विषय पर हुआ मंथन

गोरखपुर। जवाहर लाल नेहरू विश्व विद्यालय नई दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संकाय के अधिष्ठाता पद्मश्री प्रो. अमिताभ मट्टू का मानना है कि भारतीय सभ्यता और इसकी ज्ञान परंपरा वैश्विक चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम है। भारत अपने स-ांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण के माध्यम से एक मानवीय और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था को दिशा दे सकता है। प्रोफेसर मट्टू बीते सोमवार को दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस क्रम में उन्होंने विश्व व्यवस्था के सामने मौजूद -चार प्रमुख चुनौतियों का का जिक्र किया- भू-राजनीतिक बहुध्रुवीयता अस्तित्वगत संकट जैसे जलवायु परिवर्तन और महामारी तकनीक व नैतिकता और वैश्विक संस्थाओं में घटता विश्वास वैश्विक नेतृत्व पर विचार व्यक्त करते हुए प्रो. मट्टू ने कहा कि सिद्धान्तों में योगी और व्यवहार में कर्मयोगी होना चाहिए।

संगोष्ठी के समापन सत्र के मुख्य अतिथि इथोपिया में भारत के राजदूत अनिल कुमार राय ने कोरोना काल के बाद वैश्विक परिदृश्य और सतत विकास की चर्चा करते हुए कहा कि-वैश्विक नेतृत्व का आधार केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, समावेशी विकास और स्थायी प्रगति होना चाहिए। उन्होंने कौटिल्य द्वारा बताये गये तीन प्रश्नों को आत्मसात करने पर बल दिया। हम कि-सी कार्य को क्यों 'कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा और क्या यह कार्य सफल होगा? उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कुलपति पो. पूनम टंडन ने की। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक नई युग और सभ्यता के उदय का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि- भारत एक युवा-प्रधान होता है और आज की आवश्यकता कि- आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान और पारंपरिक के बीच नैतिकता - आधारित समन्वय स्थापित किया जाए। वही समन्वय भारत को वैश्विक नेतृत्व में सच्ची भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा। समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रति कुलपति शांतनु रस्तोगी ने कहा कि- हम इस संगोष्ठी के माध्यम से वर्तमान परिस्थिति में अपनी जड़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि के रूप में अधिष्ठाता कला संकाय प्रो.राजवंत राव ने भी भारतीय ज्ञान परंपरा और वैश्विक राजनीति पर अपने विचार साझा किये। संगोष्ठी मे विषय प्रवर्तन संयोजक डा. महेन्द्र कुमार सिंह ने अतिथि - स्वागत संबोधन विभागाध्यक्ष प्रो. राजेश कुमार सिंह ने और धन्यवाद ज्ञापन प्रो. गोपाल प्रसाद ने किया।

सीमा सिंह को मिलेगा मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार

लखनऊ। वर्ष 2024 के लिए मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार सीमा सिंह को उनके कविता संग्रह 'कितनी कम जगहें है के लिए किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए केपी सिंह मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष नमिता सिंह और जनवादी लेखक संघ के महासचिव नलिन रंजन सिंह ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से दिया। यह पुरस्कार आगामी 11 अक्टूबर को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान दिया जाएगा।

शिद्दत से याद किए गए जिगर मुरादाबादी

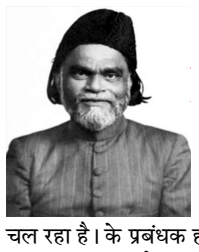

गोण्डा। देश के मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी को उनकी पुण्यतिथि पर कृतज्ञता पूर्वक याद किया गया। जिगर के रात्र पर नगर में जिगर मेमोरियल इंटर कालेज काफी समय से चल रहा है। के प्रबंधक हाजी रऊफ प्राचार्य रफी उल्लाह साहब अपने तमाम लोगों के साथ तोपखाना पहुंच कर जिगर मुरादाबादी की मजार पर खिराजे अकीदत पेश किया। लोगों ने गुलपोशी की और फातेहा पढ़ा। शाम को जिगर मुरादाबादी की याद में एक कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया गया। जिसमें जजकई मुकामी शायरों के अलावा बाहरसे आए कई शायरों ने अपनी रचनाओं से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जिगर डे को यादगार बनाया।

मुशायरे की शुरूआत शायरा - गुले सब के नात से हुआ। इसके अलावा - शायरा हिमांशी बावरा (मेरठ), निकहत मुरादाबादी, विकास बौखल अफजल इलाहाबादी, अजमल बलरामपुरी भी मंच पर मौजूद रहीं।

विश्व आत्महत्या रोकथाम सप्ताह का आगाज

आत्महत्या को नियंत्रित करने के लिए एम्स की पहल, एसओपी जारी

आत्महत्या रोकथाम कार्यशाला, चिकित्सकों व छात्रों ने आत्महत्या न करने की ली शपथ

गोरखपुर। छात्रों में आत्म हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को नियंत्रित करने और उनको मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए गत दिनों एम्स प्रशासन ने पहल करते हुए चेयर मैन (पद्मश्री) डॉ. हेमंत कुमार और कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डा. विभा दत्ता ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया? एम्स परिसर के भी छात्रों में उच्च जोखिम वाले आत्मघाती व्यवहार को संभालने और प्रतिबंधित करने के लिए यह एस ओ पी प्रारंभिक मार्गदर्शक के रूप में काम करती.. है। करेगी। साथ ही चिकित्सकों व छात्रों को आत्महत्या न करने की शपथ दिलाई गई।

डा. हेमंत कुमार ने कहा कि- पढ़ाई का तनाव नहीं लेना चाहिए। सुबह उठकर मेडिटेशन करें, दोस्तों से बात करें और फिर क्लास में जाएं। पढ़ाई कोशोक बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई समस्या हो रही है तो अपने भीतर करखें अपनी सीनियर्स को बताएं। शेयर करें।

अंदर घुट कर रहना बहुत खतरनाक होता है। हम दूसरों का जीवन बवाने आए हैं। के लिए आगे आए हैं। खुद को कैसे कमजोर कर सकते हैं। खुद को अजबूत रखें। कार्यकारी निदेशक ने कहा कि - छात्रों को आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, यदि कोई समस्या है तो उसे साझा करें ताकि उसका त्वरित निदान किया जा सके।

सूच्य है कि - एम्स (गोरखपुर) में गत 10 सितंबर से आगामी 16 सितंबर तक विश्व आत्महत्या रोकथाम सप्ताह मनाया जा रहा है जिसका विषय है- आत्म हत्या पर दृष्टिकोण बदलना है।

डेंगू पाजिटिव: रोगियों का बढ़ता ग्राफ

जांच महंगी होने के कारण रोगी नहीं करा रहे एलाइजा रिपोर्ट

गोरखपुर। डेंगू लगातार चुनौती दे रहा है। रोगी बढ़ते जा रहे है। इसका साक्ष्य बी.आर.डी. मेडिकल कालेज की जांचें हैं । रोज एक दो लोग जिलों में पाजिटिव आ रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग में ऐसा नहीं है कि विभाग में आंकड़ों में जिलों में डेंगू रोगियों की संख्या - 114 है। इनमें से मात्र 9 लोगों की रिपोर्ट जिला अस्पताल में पाजिटिव पाई गई। शेष 105 लोग मेडिकल कालेज के माइक्रो बायोलॉजी विभाग में हुई जांच में पाजिटिव पाए गये हैं। मेडिकल कालेज में बीते सोमवार को भी दो लोगों की रिपोर्ट पाजिटिव आई. इनमें से एक गोरखपुर व दूसरा कुशीनगर का बताया जा रहा है।

बताते चलें कि डेंगू रोगियों का ग्राफ भी बढ़ रहा। इसमें बीआरडी मेडिकल कालेज में उपचार करा रहे रोगियों की संख्या बढ़ी है। जिला अस्पताल सी सीएचसी पीएचसी पर पहुंच रहे बुखार के रोगियों की डेंगू जांच बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्र में 18 ब्लाकों व शहर में 21 क्षेत्रों में डेंगू रोगी मिल चुके हैं। ये रोगी हैं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग भी डेंगू पाज़िटिव मानता है क्यों-कि एलाइजा जांच हुई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में बुखार के रोगी डेंगू की रैपिड जांच रिपोर्ट आने पर उपचार को प्राथमिकता दे रहे हैं जांचें महंगी होने के नाते वे एलाईजा जांच नहीं करा रहे हैं और निजी चिकित्सकों के यहां इलाज करा रहे हैं। इन रोगियों की संख्या विभाग के डाटा में शामिल नहीं है।

गोरखनाथ मंदिर में प्रातः कालीन भ्रमण के दौरान मोर को दाना चुगात येणी आदित्यनाथ।

पुस्तक विमोचन:

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री- योगी आदित्य नाम ने. काशी हिंदू विश्व विद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के आचार्य प्रो. ओंकारनाथ सिंह की पुस्तक 'भारतीय संस्कृति की आत्म साती प्रकृति' और महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल धूषड़ के परम पूज्य संत द्वय (महंत दिग्विजय नाथ एवं महंत अवैध नाथ) को समर्पित मासिक पत्रिका विमर्श का विमोचन किया। अतिथियों का स्वागत महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश मोहन सरकार और संचालन डा. श्रीभगवान सिंह ने किया। वैदिक मंगलाचरण - डा. रंगनाथ त्रिपाठी. गोरक्षाष्टक पाठ गौरव तिवारी व आदित्य पाण्डेय, और दिग्विजय स्तोत पाठ- डॉ. अभिषेक ने किया।

साहित्य जगत में अपनी अलग पहचान बनाती कृति समर्पण

कवि व रचनाकार शिवलाल दांगी की काव्य कृति समर्पण पढ़ने को मिली।जिसे मैंने प्रारम्भ से अंत तक पढ़ा।कवि शिवलाल दांगी कवि होने के साथ ही श्रेष्ठ शिक्षाविद भी है।लगभग 19 वर्षों से आप राज्य स्तरीय हिंदी प्रशिक्षक हैं।आप हिंदी व्याकरण में सिद्धहस्त हैं।ओजस्वी वाणी के धनी ,नवाचारी शिक्षक के रूप में भी आपके व्यक्तित्व की पहचान है।आपकी सैंकड़ों रचनाएँ अब तक देश के विभिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है।

प्रस्तुत कृति में 102 छन्दमुक्त काव्य रचनाएँ शामिल हैं। 150 पृष्ठों की इस काव्य कृति में परिवेश से जुड़ी घटनाओं,समस्याओं पर आधारित कविताएं हैं। आपकी इन कविताओं में बाहरी दिखावा भौतिक-वाद, शहरीकरण का विरोध देखा जा सकता है।आपकी कविताएं युवा वर्ग को नेक राह पर चलने का संदेश देती है।निम्नवर्ग के लोगों के साथ आप खड़े मिलते हैं वहीं नौकरशाही के प्रति आपकी असहमति इन कविताओं में जाहिर होती है।

कवि शिवलाल दांगी पर्यटन प्रेमी है।आपने विभिन्न प्रान्तों के साथ नेपाल,भूटान की यात्राएं की है।इन कविताओं में आपने अपने अनुभव साझा किए हैं।अवार्चीन काल मे व्याप्त सामाजिक विसंगतियों पर आपने पैनी कलम चलाई है।

काव्य संग्रह 'समर्पण'में आशा ओर सकारत्मकता के साथ सामाजिक मुद्दों को आपने उठाया है।इसकी भाषा प्रवाहपूर्ण,सरल,स्पष्ट व बोधगम्य है।

काव्य संग्रह में वर्णित कविताओं में लय,ताल शब्द शक्ति व काव्य गुणों का समावेश देखते ही बनता है।कवि की काव्य भाषा और संवेदना के शिल्प की जितनी प्रशंसा की जाए कम है।

इस कृति का मूल उद्देश्य जनसाधारण में संस्कारों का बीजारोपण करना है।आपने यह काव्य संग्रह अपने स्वर्गीय पूज्य पिता तेजमल जी दांगी व माता स्वर्गीय श्रीमती सरदारबाई को समर्पित किया है।

प्रस्तुत कृति में जीवन के विविध रंगों का इन कविताओं में सुन्दर संयोजन देखा जा सकता है।ये कविताएं निराशा से उबारकर जीवन मे नई उमंग,नई उम्मीद ओर हौंसलों के साथ जीवन संघर्ष करते हुए जीने की कला सिखाती है।

काव्य संग्रह समर्पण की ये कविताएं कवि के हृदय की भावनाओं को कागज पर उकेरी हुई संदेशपरक कविताओं का सुन्दर गुलदस्ता है। समर्पण की प्रथम कविता वैराग्य है वहीं अंतिम कविता मृदुमयवाणी है।

वैराग्य कविता में कवि लिखता है-

जीवन के अंतिम दिनों में,
मेरे मन में वैराग्य आया।
जीवन भर छलती रही,
असहाय अब यह काया।

वस्तुतः हम सारी उम्र यूँ ही मोह माया के जाल में गुजार देते हैं।उम्र कब गुजर जाती है।चौथेपन में वैराग्य आता है जब रोग घेर लेते हैं। ईश्वर की माला जपने में मन नहीं लगता है।समय रहते इसलिए ईश्वर का सुमिरन कर लेना चाहिए।

इंसानियत शीर्षक से लिखी कविताओ की पंक्तियां देखिए-

मानवीय मूल्यों से दूर,
बचे कहाँ अब संस्कार
अपने लालच के कारण,
बिखर गए सब परिवार।

आज टूटते बिखरते परिवार देखकर कवि को चिंता

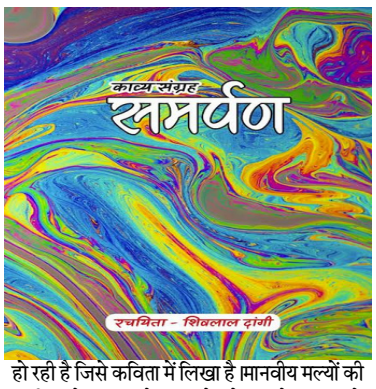

हो रही है जिसे कविता में लिखा है।मानवीय मल्यों की कमी,टूटते परिवार के कारणों को आपने कविता में लिखा है।आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। एकल परिवार बनते जा रहे हैं।

बढ़ता भ्रष्टाचार कविता में देश मे व्याप्त इस समस्या को आपने बेबाकी से लिखा है। जीवनसूत्र कविता में इच्छाओं पर नियंत्रण रखने से सुख से रहा जा सकता है बहुत सटीक संदेश दिया है।

बचपन का गाँव कविता पढ़कर आपने गांव की याद दिला दी।खग कलरव सुन्दर प्रकृति स्वतंत्रता स्वच्छ पर्यावरण ये सब है आज भी गांवों में।कवि लिखता है- पशु पक्षियों सी स्वछंद,जिंदगी जीना चाहता हूं।बंदिशों का भार हटाकर,मैं गाँव जाना चाहता हूं। शहरों में सूनापन,अकेलापन व्यर्थ की दौड़-भाग भौतिकता की चमक दमक में इंसान दो घड़ी शांति की गुजारना चाहता है। आज लोग शहरों से गाँव जाने की सोचने लगे हैं।

मिलावट कविता में कवि लिखता है-

राशन कोई शुद्ध नहीं,
लगता हो रही मिलावट।
सुनता कौन यहाँ किसकी,
कर रहे सब ही दिखावा।

आज व्यर्थ का दिखावा लोग करते हैं।आज बाजार में सब चीजों में मिलावट आ रही है जो चिंताजनक है।आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।

गम और खुशी कविता में बताया है कि प्रसन्नता इस जगत में सफलता की कुंजी है। व्यक्ति को हर हाल में खुश रहना चाहिए।व्यर्थ तनाव नहीं लेना चाहिए।

अर्थ की चाह कविता में कवि कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं।घर परिवार को भूलते जा रहे हैं।बस व्यक्ति का उद्देश्य जैसे अब धन अर्जित करना रह गया है।

चुनौती स्वीकार करो कविता में कवि ने संदेश दिया कि कोई भी चुनोती आपको मिले उससे डरना घबराना नहीं चाहिए।धैर्य से काम लेना चाहिए।अपने कौशल से शक्ति से मिली हुई चुनोती का हल भी निकल जाता है।

दीपक कविता में कवि शिवलाल दांगी लिखते हैं-

खुद में ही जलता रहता,
भाव मेरा सब निराला।
अंधकार का डर मिटाकर,
चहुँ ओर करता उजाला।
दीपक खुद जलकर
दूसरों को उजाला देता है।
व्यक्ति वही है जो दूसरों के लिए
जन हितार्थ कार्य करे।

सुकून कविता की सुन्दर पंक्तियां देखिए-

रिश्तों में मिले अपनत्व,
जिंदगी को जो सुकून देता।
झूंठे जगत का मायाजाल,
अपना सुख चैन हर लेता।

जहाँ तक परिवार के भीतर रिश्तों में आपसी मिठास अपनत्व रहता है जिंदगी में शांति रहती है लेकिन इस मिथ्या जगत के मायाजाल में फंसने के बाद सुख चैन सब खो जाता है।

लाचार आदमी कविता में कवि ने रिश्वत खोरी के बारे में लिखा कि बिन रिश्वत काम न होता,रिश्वतखोर खास हो गया। बहुत सुंदर व्यंग्यात्मक शैली में आपने कविता लिखी है।

लक्ष्य कविता में शाकाहार को बढावा देने की सलाह दी है। तुम सा मीत नहीं कविता की पंक्तियां दिल को छू गई- तुम जीवन भर साथ रहे,तुम सा जग में मीत नहीं। तुम्हें भुलाकर होती यहाँ,मेरी कोई जीत नहीं।सच्ची मित्रता के गुण इस कविता में बताए गए हैं।

इस काव्य संग्रह की अंतिम कविता मृदुमयवाणी में कवि संदेश देता है कि सबके प्रति वाणी में भाव हमारा मधुर रहना चाहिए।जिन लोगों से आपकी शत्रुता हो उनसे भी मीठे वचन बोलें।

इस कृति की जीवन सार बंटवारा प्राचीन चिकित्सा विज्ञान जैसी कविताएं भी अच्छी लगी। संक्षेप में यह काव्य संकलन संदेशपरक है जो भाग-दौड़ की जिंदगी से दूर शांति व सुख से जीवन जीने की सीख देता है। सभी कविताएं भावपूर्ण है।

समीक्षक -
डॉ. राजेश कुमार शर्मा पुरोहित
भवानीमंडी, झालावाड़
राजस्थान

घूँघट की बगावत

14 सितम्बर 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

नेपाल का लोकतंत्र: पुराने वर्चस्व से नई चुनौती तक

नेपाल हिमालय की गोद में बसा छोटा-सा देश है। आकार में भले छोटा हो, लेकिन राजनीति और जातीय समीकरण के लिहाज से इसकी जटिलता किसी बड़े देश से कम नहीं। नेपाल पिछले तीन दशकों से लोकतंत्र का प्रयोग कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह लोकतंत्र अब भी अधूरा है। सत्ता और संसाधनों पर एक ही वर्ग का कब्जा है—पहाड़ी ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियाँ। संसद से लेकर प्रशासन और सेना तक, हर जगह यही जातियाँ हावी हैं। मधेशी, जनजातीय, दलित और महिलाएँ अब भी सत्ता की सीढ़ियों के निचले पायदान पर खड़ी हैं। 1990 में नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी हुई थी। जनता को उम्मीद थी कि अब सत्ता में विविधता आएगी और हर समुदाय को बराबरी का अवसर मिलेगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 1990 से अब तक नेपाल ने 13 प्रधानमंत्री देखे। इनमें से 10 पहाड़ी ब्राह्मण और 3 क्षत्रिय रहे। यानी 35% मधेशियों की आबादी होने के बावजूद एक भी मधेशी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। जनजातीय और आदिवासी समूह संसद में मौजूद हैं, लेकिन उनके नेता केवल प्रतीकात्मक पदों तक सीमित रहे। दलित और महिलाएँ तो आज भी सत्ता के सबसे हाशिये पर खड़ी हैं। यह तस्वीर बताती है कि नेपाल का लोकतंत्र कितनी गहरी जातीय असमानता से ग्रस्त है। लोकतंत्र के नाम पर चेहरे तो बदले, लेकिन सत्ता का चरित्र वही रहा—ब्राह्मण और क्षत्रिय केंद्रित। नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यही वह नई पीढ़ी है जिसे जनरेशन- कहा जाता है। यह सोशल मीडिया, पॉप कल्चर और वैश्विक राजनीति से जुड़ी हुई है। इनके लिए जाति और वंश की राजनीति पुरानी और अप्रासंगिक है। यह पीढ़ी पारदर्शिता चाहती है, समान अवसर चाहती है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बदलाव को केवल सोचती नहीं बल्कि मांग भी करती है। यही कारण है कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह आज नेपाल के युवाओं के बीच परिवर्तन का प्रतीक बन चुके हैं। 2022 में जब बालेन शाह ने काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता तो यह केवल एक चुनाव नहीं था, बल्कि सत्ता की पुरानी धारणाओं पर सीधी चोट थी। काठमांडू दशकों से मुख्यधारा की पार्टियों—नेपाली कांग्रेस, वटछ और माओवादी केंद्र—का गढ़ माना जाता था। लेकिन शाह ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सबको चौंका दिया। वे न तो परंपरागत राजनीति से आए थे और न ही किसी जातीय वंश से जुड़े थे। उनकी पृष्ठभूमि हिप-हॉप कलाकार और इंजीनियर की थी। वे मधेशी भी हैं और बौद्ध भी। यानी हर लिहाज से नेपाल की मुख्यधारा की राजनीति से बिल्कुल अलग। उनकी जीत ने यह संदेश दिया कि जनता अब विकल्प चाहती है। खासकर युवा पीढ़ी, जो बार-बार जातीय गणित से चलने वाली राजनीति से ऊब चुकी है। बालेन शाह का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। वे सोशल मीडिया पर बेहद

सक्रिय हैं और सीधा संवाद करने का तरीका जानते हैं। नेपाल की मौजूदा राजनीति जहाँ अभी भी भाषण और रैलियों पर निर्भर है, वहीं शाह डिजिटल युग की राजनीति कर रहे हैं। उनका संगीत, उनकी स्पष्ट बातें और उनकी स्वतंत्र छवि युवाओं को तुरंत आकर्षित करती है। यह फर्क बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल की राजनीति में पहली बार कोई ऐसा चेहरा सामने आया है जो राजनीति को कूल बना रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या नेपाल की पुरानी सत्ता संरचना इतनी आसानी से टूट जाएगी? नेपाली कांग्रेस, वटछ और माओवादी जैसे दल दशकों से सत्ता पर काबिज हैं। इनके नेता ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय से आते हैं और इनकी पकड़ प्रशासन, सेना और नौकरशाही तक फैली हुई है। यह पूरा ढांचा बालेन शाह जैसे किसी नेता के लिए दीवार की तरह खड़ा हो सकता है। संभावना है कि शाह को ह्लअनुभवहीनह्व या ह्लपॉपुलिस्टह्व कहकर खारिज करने की कोशिश की जाएगी। उनकी स्वतंत्र पहचान पर सवाल उठाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में बैठे लोग कभी आसानी से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते।अगर नेपाल बालेन शाह जैसे नेता को प्रधानमंत्री बनने का मौका देता है, तो यह केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं होगी, बल्कि ऐतिहासिक होगा। नेपाल पहली बार किसी गैर-ब्राह्मण/क्षत्रिय प्रधानमंत्री को देखेगा। यह संदेश जाएगा कि लोकतंत्र केवल नाम का नहीं बल्कि वास्तविक रूप से समावेशी है। मधेशी, जनजातीय और दलित समुदाय को यह विश्वास मिलेगा कि सत्ता में उनकी भी हिस्सेदारी है। युवाओं को लगेगा कि उनकी आवाज मायने रखती है। लेकिन अगर बदलाव की इस मांग को दबाया गया, तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। युवा पीढ़ी पहले ही अधीर है। वे सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी और सपनों को साझा कर रहे हैं। अगर उनकी आवाज दबाई गई, तो असंतोष सड़क पर आंदोलन में बदल सकता है। नेपाल ने पहले भी जनआंदोलन देखे हैं और इतिहास गवाह है कि जब जनता चाहती है, तो कोई भी सत्ता ढांचा स्थायी नहीं रह पाता।

नेपाल आज दो राहों पर खड़ा है। एक तरफ पुरानी राजनीति है, जहाँ सत्ता कुछ जातियों के बीच बंटी हुई है। दूसरी तरफ नई राजनीति है, जो समावेशी, पारदर्शी और युवाओं से जुड़ी है। बालेन शाह इस बदलाव का प्रतीक हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि शाह प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या नेपाल जातीय ढांचे वाली राजनीति से आगे बढ़ पाएगा या नहीं। अगर नेपाल यह कदम उठाता है, तो वह दक्षिण एशिया में एक मिसाल बन सकता है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी राजनीति अक्सर वंशवाद और जातीय समीकरण में उलझी रहती है। नेपाल अगर इस ढांचे से बाहर निकलता है, तो यह पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा होगी। लेकिन अगर पुरानी सत्ता संरचना कायम रहती है, तो लोकतंत्र अधूरा ही रहेगा। युवाओं का भरोसा टूटेगा और यह भरोसा टूटना किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। नेपाल की राजनीति दशकों से पहाड़ी ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के कब्जे में रही है। लोकतंत्र आया, चेहरे बदले, लेकिन चरित्र वही रहा। आज की पीढ़ी इसे चुनौती दे रही है। बालेन शाह इसका चेहरा हैं। यह पीढ़ी जाति, वंश और सत्ता के पुराने ढांचे को स्वीकार नहीं करना चाहती। नेपाल का लोकतंत्र अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। या तो यह समावेशी होकर सबको बराबरी देगा, या फिर पुरानी असमानता को जारी रखेगा। भविष्य का फैसला अब नेपाल की नई पीढ़ी के हाथ में है और उनकी मांग साफ है—अबकी बार राजनीति सबकी, सिर्फ ब्राह्मण-छत्री की नहीं।

डॉ. सत्यवान सौरभ

अनिश्चित भविष्य एवं आभासी दुनिया से दुःखी युवा पीढ़ी

पूरी दुनिया की सरकारें युवा के मुद्दों, उनमें बढ़ रहे तनाव एवं दुःखों और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करे। न केवल सरकारें बल्कि आम-जनजीवन में भी युवकों की स्थिति, उनके सपने, उनके जीवन लक्ष्य आदि पर चर्चाएं हो, अन्यथा युवकों की जीवनशैली में रचनात्मक परिवर्तन के स्थान पर हिंसा-आतंक-विध्वंस की स्थितियां विकराल होती जायेगी, जैसाकि नेपाल में देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दशकों तक यह मान्यता रही कि जीवन की मध्य आयु वर्ग यानी 40 से 50 वर्ष के लोग ही सबसे अधिक अवसादग्रस्त, तनावग्रस्त, क्रोधित और दुखी होते हैं। युवावस्था और बुजुर्गावस्था अपेक्षाकृत अधिक प्रसन्न और संतुलित मानी जाती थी। लेकिन हाल के वैश्विक अध्ययनों ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखने वाली ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट सहित अनेक शोध बताते हैं कि दुख और तनाव की शुरूआत अब युवावस्था से ही होने लगी है। सबसे खुशी, मस्त एवं तनावमुक्त जीवन जीने वाली यह पीढ़ी अब सबसे अधिक तनावग्रस्त हो गयी है, जो गहन चिन्ता का सबबे है। अमेरिका, ब्रिटेन, एशिया, अफ्रीका और मध्यपूर्व जैसे 44 देशों के आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आज की युवा पीढ़ी बुजुर्गों से भी अधिक कमजोर है। युवाओं की इस स्थिति के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे रोजगार की असुरक्षा, भविष्य की अनिश्चितता, कार्यस्थलों का दबाव, प्रतिस्पर्धा का वातावरण और सबसे बड़ा कारक सोशल मीडिया का बढ़ता हस्तक्षेप। आभासी दुनिया युवाओं को बड़े सपने तो दिखाती है, लेकिन जीवन की कठोर सच्चाइयों से उनका सामना नहीं कराती। यही कारण है कि वास्तविक चुनौतियों से टकराते ही वे टूटने लगते हैं। आज के युवा सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं। देर रात तक स्क्रीन से चिपके रहना उनकी नींद और दिनचर्या दोनों को प्रभावित कर रहा है। आभासी मित्रता और लाइक्स की दुनिया में उन्हें वास्तविक संबंधों की गर्मजोशी नहीं मिल पाती। संवाद की जगह इमोजी ले लेते हैं और भावनाओं का स्थान कृत्रिम पोस्ट। परिणामस्वरूप वे वास्तविक सामाजिक जीवन से कटते जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब इंसान अपने मित्रों, परिवार और समाज के साथ आमने-सामने संवाद करता है, तो तनाव कम होता है। कृतज्ञता का भाव मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। परंतु डिजिटल आभामंडल में जीने वाला युवा जब अपनी तुलना लगातार दूसरों की सफलता और भौतिक समृद्धि से करता है, तो उसमें हीनभावना और निराशा जन्म लेती है। यही निराशा कई बार आक्रोश और हिंसा का रूप ले लेती है। सवाल यह है कि मानसिक तनाव का सीधा रिश्ता हिंसा से कैसे जुड़ रहा है। दरअसल, जब कोई व्यक्ति भीतर से असुरक्षित, असंतुष्ट और हताश होता है तो उसकी ऊर्जा रचनात्मकता की बजाय विध्वंसक रास्ते पकड़ लेती है। जिन युवाओं को उचित दिशा, रोजगार और सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाती, वे गुस्से में समाज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही गुस्सा कई बार सामाजिक अशांति, अपराध और दंगों के रूप में सामने आता है। यह वैश्विक ट्रेंड केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और विशेष रूप से नेपाल में हालिया परिदृश्य इसका उदाहरण है। नेपाल में पिछले महीनों हुए दंगे, हाल की युवाक्रांति और युवा आंदोलनों ने इस सच्चाई को सामने ला दिया कि निराशा से भरे युवाओं की ऊर्जा किस तरह हिंसा और अराजकता का रूप ले सकती है। नेपाल का इतिहास ही युवा आंदोलनों से भरा रहा है। राजतंत्र से लोकतंत्र और फिर लोकतांत्रिक अस्थिरता के बीच युवा हमेशा निर्णायक शक्ति रहे हैं। हाल ही में नेपाल में हुए दंगों और विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में भी युवा ही थे। नेपाल के युवा लंबे समय से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। वहां की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा 30 वर्ष से कम आयु का है, लेकिन रोजगार और अवसरों की कमी उन्हें या तो प्रवासी मजदूरी की ओर धकेल रही है या फिर हिंसक आंदोलनों की ओर। सोशल मीडिया इस असंतोष को और हवा दे रहा है। एक तरफ वहां पर नई राजनीतिक चेतना के स्वर सुनाई देते हैं, दूसरी तरफ यह चेतना जब रचनात्मक दिशा नहीं पाती तो दंगे, हिंसा और अराजकता का रूप ले लेती है। नेपाल के हालिया आंदोलन यह भी बताते हैं कि युवा सिर्फ रोजगार और आर्थिक अवसर ही नहीं चाहते, वे सामाजिक न्याय, ईमानदार एवं भ्रष्टाचारमुक्त शासन और राजनीतिक स्थिरता की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन जब इन मांगों को अनसुना किया जाता है, तो वही आक्रोश सड़क पर हिंसा के रूप में फूट पड़ता है। यदि हम नेपाल की घटनाओं को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है। यह उस वैश्विक संकट की झलक है जिसमें पूरी दुनिया की युवा पीढ़ी फंसी हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भी 2016 के बाद से चालीस वर्ष से कम उम्र के युवाओं में अवसाद और चिंता बढ़ी है। एशिया और अफ्रीका जैसे विकासशील देशों में रोजगार की असुरक्षा ने युवाओं को और हताश किया है।

शिक्षा सुधार का अधूरा सपना या केवल राजनीतिक नारा?

सरकार ने घोषणा की थी कि इस वर्ष तबादले अप्रैल में होंगे, किंतु सितंबर तक भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। यह देरी न केवल शिक्षकों के साथ वादाखिलाफी है, बल्कि छात्रों की पढ़ाई और विद्यालयों के संचालन पर भी सीधा आघात है। हरियाणा सरकार की ह्लड्रीम पॉलिसीह्व का उद्देश्य था शिक्षक तबादलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना। शुरूआत में इसे क्रांतिकारी कदम माना गया, लेकिन अब बार-बार शेड्यूल में देरी, तकनीकी पेचीदगियों और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण यह विवादों में घिर गई है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार ने केवल औपचारिकताएँ थोपकर वादाखिलाफी की है। इसका असर सीधे शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई न हुई तो यह नीति उपलब्धि न बनकर सरकार की विफलता का प्रतीक बन जाएगी।

हरियाणा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से कुछ वर्ष पूर्व शिक्षक तबादलों के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू की थी, जिसे बड़े गर्व से ह्लड्रीम पॉलिसीह्व का नाम दिया गया। इस नीति को लागू करने का तात्पर्य यह था कि अब शिक्षकों के तबादले केवल वरिष्ठता, मेरिट और प्राथमिकताओं के आधार पर होंगे, न कि सिफारिश या दबाव से। आरंभ में इसे एक क्रांतिकारी कदम माना गया। किंतु बीते वर्षों में इस नीति की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि इस वर्ष तबादले अप्रैल में होंगे, किंतु सितंबर तक भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। यह देरी न केवल शिक्षकों के साथ वादाखिलाफी है, बल्कि छात्रों की पढ़ाई और विद्यालयों के संचालन पर भी सीधा आघात है। शिक्षा केवल विद्यालय भवन या पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर नहीं करती; उसकी वास्तविक धुरी शिक्षक ही हैं। हरियाणा जैसे राज्य में, जहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में स्पष्ट असमानता है, वहाँ शिक्षकों की उचित तैनाती अत्यंत आवश्यक हो जाती है। ग्रामीण अंचलों के विद्यालय अक्सर योग्य और अनुभवी शिक्षकों से वंचित रहते हैं, जबकि शहरी विद्यालयों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में शिक्षक तैनात मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में तबादला नीति मात्र प्रशासनिक प्रक्रिया न होकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का एक सशक्त साधन बन जाती है।

सरकार ने दावा किया था कि ड्रीम पॉलिसी से भ्रष्टाचार और पक्षपात का अंत होगा। परंतु, वास्तविकता यह है कि नीति का क्रियान्वयन अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहा है। शिक्षकों को बार-बार एमआईएस अपडेट कराने के निर्देश दिए गए, जिनमें व्यक्तिगत विवरणों से लेकर मोबाइल नंबर तक शामिल रहे। दोहराई जाने वाली इन औपचारिकताओं ने असंतोष को जन्म दिया और तकनीकी त्रुटियों व डेटा की गलतियों ने पारदर्शिता के दावे पर प्रश्न खड़े किए। इसके साथ ही सबसे गंभीर शिकायत यह रही कि समय पर ट्रांसफर शेड्यूल जारी नहीं किया गया। इस देरी के कारण न केवल शिक्षकों के निजी जीवन पर प्रभाव पड़ा, बल्कि विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियाँ भी बाधित हुईं। भले ही प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन बताया गया, परंतु शिक्षकों का आरोप है कि आज भी रसूख और सिफारिशों का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हाल ही में कैथल में हुई बैठक में शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही ट्रांसफर शेड्यूल जारी नहीं किया गया तो सरकार की ड्रीम पॉलिसी स्वयं सरकार के लिए ही बदनामी का कारण बन जाएगी। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें अनावश्यक औपचारिकताओं में उलझा रखा है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कई बार आश्वासन दे चुके हैं, किंतु अब तक वादे पूरे नहीं हुए। शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया को जानबूझकर लंबित रखता है। यह असंतोष केवल तबादलों तक सीमित न रहकर सरकार की नीयत और वादाखिलाफी पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। यदि कोई यह मान ले कि यह विवाद केवल शिक्षकों के हितों तक सीमित है, तो यह गंभीर भूल होगी। अनेक विद्यालय रिक्तियों से जूझते हैं और छात्रों की पढ़ाई प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। बार-बार के विलंब और वादाखिलाफी से शिक्षकों का मनोबल टूटता है। असंतुष्ट शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित योगदान नहीं दे पाते। जब स्वयं शिक्षक ही नीति पर भरोसा न करें तो समाज और विद्यार्थियों का विश्वास स्वतः डगमगा जाता है।

हरियाणा की राजनीति में शिक्षा सदा ही प्रमुख विषय रही है। सरकारें शिक्षा सुधार के दावे करती रही हैं, किंतु शिक्षक भर्ती, तबादला और पदस्थापन सबसे विवादित मुद्दे बने रहे हैं। ड्रीम पॉलिसी का विवाद अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताते हुए जनता के बीच उभारने की तैयारी में है। यदि यह असंतोष बढ़ा तो आगामी चुनावों में यह मुद्दा सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। सरकार के पास अभी अवसर है कि वह इस नीति को वास्तव में ह्लड्रीम पॉलिसीह्व बनाए। इसके लिए ट्रांसफर प्रक्रिया का स्पष्ट कैलेंडर बनाना और उसका पालन करना आवश्यक है। एमआईएस और अन्य ऑनलाइन तंत्र को अधिक सरल व विश्वसनीय बनाना होगा। प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित और मेरिट-आधारित बनाया जाए तथा शिक्षकों के संगठनों से नियमित संवाद स्थापित किया जाए। निर्णय प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी, उतना ही विश्वास बहाल होगा। हरियाणा की ड्रीम पॉलिसी का उद्देश्य प्रशंसनीय था, किंतु इसके क्रियान्वयन में गंभीर कमियाँ सामने आई हैं। यदि सरकार ने इन्हें शीघ्र दूर नहीं किया तो यह नीति सरकार की उपलब्धि न बनकर उसकी विफलता का प्रतीक सिद्ध होगी। शिक्षा किसी भी समाज की आधारशिला है और शिक्षक उसकी नींव। यदि शिक्षक ही असंतुष्ट और उपेक्षित रहेंगे, तो शिक्षा सुधार का सपना अधूरा रह जाएगा। अतः आवश्यक है कि सरकार वादों से आगे बढ़कर वास्तविक कार्रवाई करे, ताकि हरियाणा की ड्रीम पॉलिसी सचमुच ह्लसपनों की नीतिह्व सिद्ध हो सके, न कि केवल एक राजनीतिक नारा।

- डॉ. सत्यवान सौरभ,

ग्रामीण साक्षरता: जमीनी स्वयंसेवक साक्षरता को कैसे बढ़ा सकते हैं

विजय गर्ग

ग्रामीण भारत में, साक्षरता केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता से अधिक है, जो आजीवन सीखने और आजीविका की नींव प्रदान करती है। फिर भी, दशकों की प्रगति के बावजूद, अल्पविकसित समुदायों में बड़ी संख्या में बच्चे मूलभूत पढ़ने के कौशल के साथ संघर्ष करना जारी रखते हैं। सही उम्र में धाराप्रवाह पढ़ने में असमर्थता न केवल अकादमिक प्रदर्शन को बाधित करती है, बल्कि जीवन में बाद में अवसरों के लिए दरवाजे भी बंद कर देती है, उच्च शिक्षा से लेकर सम्मानजनक रोजगार तक।

अकेले स्कूल इस अंतर को पाट नहीं सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कम-से-कम, एक एकल शिक्षक को विभिन्न पढ़ने के स्तर पर, 30-40 बच्चों के कई ग्रेड या कक्षाओं को संभालने के साथ काम किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को पूरा करने का दबाव व्यक्तिगत ध्यान के लिए बहुत कम जगह छोड़ देता है। नतीजतन, कई बच्चों को बुनियादी साक्षरता में महारत हासिल किए बिना साल-दर-साल पदोन्नत किया जाता है, जिससे सीखने की कमी पैदा होती है जो केवल समय के साथ चौड़ी होती है। एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है जो समुदायों को जुटाता है, पुस्तकों तक पहुंच को मजबूत करता है, और जमीन से पढ़ने की संस्कृति का पोषण करता है। यहां, जमीनी स्वयंसेवक एक अमूल्य भूमिका निभा सकते हैं। स्थानीय युवा, महिलाएं या सेवानिवृत्त शिक्षक अपने समुदायों के भीतर चैंपियन पढ़ने के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। वे न केवल पढ़ने के सत्रों का नेतृत्व करते हैं और बच्चों को कहानियों का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत सहायता भी प्रदान करते हैं जो कक्षाएं अक्सर नहीं कर सकती हैं। स्वयंसेवक अपने पढ़ने के स्तर के अनुसार बच्चों को समूहीकृत करके, केंद्रित इनपुट देकर, प्रगति की निगरानी और सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देकर अंतर को पालते हैं। यह अनुरूप दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा पीछे न रहे और प्रत्येक छात्र अपनी गति से पढ़ने के कौशल को मजबूत कर सके। प्रथम द्वारा वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट (अरएफ)

ग्रामीण भारत में साक्षरता केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता से अधिक है, जो आजीवन सीखने और आजीविका की नींव प्रदान करती है। फिर भी, दशकों की प्रगति के बावजूद, अल्पविकसित समुदायों में बड़ी संख्या में बच्चे मूलभूत पढ़ने के कौशल के साथ संघर्ष करना जारी रखते हैं। सही उम्र में धाराप्रवाह पढ़ने में असमर्थता न केवल अकादमिक प्रदर्शन को बाधित करती है, बल्कि जीवन में बाद में अवसरों के लिए दरवाजे भी बंद कर देती है, उच्च शिक्षा से लेकर सम्मानजनक रोजगार तक।

2024 में इस कार्य की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला गया है, जिस-से पता चलता है कि प्रगति के बावजूद, ग्रामीण सीखने में लगातार अंतराल बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, कक्षा ~~क~~कक के सरकारी स्कूली बच्चों की कक्षा ~~क~~क-स्तरीय पाठ पढ़ने में सक्षम हिस्सेदारी 2022 में 16.3 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 23.4 प्रतिशत हो गई, अरएफ शुरू होने के बाद से उच्चतम स्तर। कक्षा के छात्रों में, पढ़ना प्रवाह एक ही अवधि में 38.5 प्रतिशत से बढ़कर 44.8 प्रतिशत हो गया। ये आंकड़े इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि मूलभूत साक्षरता में सुधार हो रहा है, लेकिन बच्चों के बड़े वर्ग में अभी भी ग्रेड-स्तर के कौशल की कमी है, जो समुदाय-संचालित, स्वयंसेवक के नेतृत्व वाले पठन हस्तक्षेपों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। पुस्तकों तक पहुंच एक और महत्वपूर्ण एनबलर है। उम्र-उपयुक्त और आकर्षक सामग्री के साथ स्टॉक किए गए छोटे, स्कूल या समुदाय-आधारित पुस्तकालय कक्षा के बाहर पढ़ने की आदत बनाने में मदद करते हैं।

जब बच्चे उन कहानियों के संपर्क में आते हैं जो उनकी वास्तविकताओं को दर्शाती हैं या उनकी कल्पना को चिंगारी देती हैं, तो पढ़ने का आनंद आत्मनिर्भर हो जाता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के आसपास के गांवों के साक्ष्य, जो संभव है उसकी झलक प्रदान करते हैं। एक ग्रामीण रीडिंग प्रमोशन प्रोग्राम, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था और 2022-2024 के बीच मूल्यांकन किया गया था, ने सभी ग्रेड में पढ़ने में लगातार ऊपर की ओर रुझान का खुलासा किया, सामुदायिक स्वयंसेवकों को 'पुस्तक परियों' कहा जाता है।

दो कारक सबसे दृढ़ता से सुधार से जुड़े के रूप में उभरे: पढ़ने के सत्रों की संख्या में भाग लिया और पुस्तकों की संख्या पढ़ी। जो छात्र एक वर्ष से अधिक समय तक कार्यक्रम में रहे, उन्होंने न केवल तेजी से सुधार किया, बल्कि अपने साथियों की तुलना में उच्च पढ़ने के स्तर पर बाद के शैक्षणिक वर्षों की शुरूआत की, इस तथ्य का प्रदर्शन किया कि समुदाय समर्थित साक्षरता कार्यक्रम एक शानदार प्रभाव पैदा करते हैं। एक बार जब एक बच्चा पढ़ने में आत्मविश्वास बनाता है, तो अन्य विषयों के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता में भी सुधार होता है। ऐसे मॉडल साबित करते हैं कि परिवर्तन को महंगा नहीं होना चाहिए। निरंतर स्वयंसेवक भागीदारी, पुस्तकों तक स्थिर पहुंच और नियमित प्रोत्साहन के साथ, साक्षरता परिणामों में कम लागत पर नाटकीय रूप से सुधार किया जा सकता है। गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों की इस मॉडल को स्केल करने, प्रशिक्षण और संसाधनों के साथ स्वयंसेवकों का समर्थन करने और निगरानी के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण साक्षरता केवल एक शिक्षा चुनौती नहीं है; यह एक विकास अनिवार्य है। जो बच्चे पढ़ सकते हैं, वे स्कूल में रहने, उच्च अध्ययन करने, कौशल के अवसरों का उपयोग करने और सार्थक आजीविका को सुरक्षित करने की अधिक संभावना रखते हैं। समुदायों के लिए, साक्षरता ईंधन सशक्तिकरण, आवाज और एजेंसी को मजबूत करती है, और गरीबी के चक्र को तोड़ने में मदद करती है। आगे का रास्ता स्पष्ट है: भारत को न केवल कक्षाओं और शिक्षकों में बल्कि स्वयं समुदायों की शक्ति में भी निवेश करना चाहिए। स्थानीय स्वयंसेवकों को पढ़ने के चैंपियन के रूप में उपयोग करके और पुस्तकों तक पहुंच के साथ पढ़ने की आदतों को एम्बेड करके, हम भारत के ग्रामीण बच्चों के लिए एक मजबूत नींव रख सकते हैं।

मलोट पंजाब

वन पंचायतों के सशक्तिकरण विषयक कार्यशाला

मानसखंड विज्ञान केंद्र में बनेगा कार्बन क्रेडिट मूल्यांकन सेल : प्रोफेसर पंत

अल्मोड़ा। मानसखंड विज्ञान केंद्र सुनौला स्यालीद्धार अल्मोड़ा में वन पंचायतों के सशक्तिकरण विषय पर बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यशाला में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, पर्यावरणविदों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।

यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने नॉन टिंबर फारेस्ट के आकलन के लिए तकनीक के इस्तेमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि मानसखंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा में कार्बन क्रेडिट मूल्यांकन सेल की स्थापना की जाएगी। इससे पूरे क्षेत्र के वनों के कार्बन क्रेडिट का मूल्यांकन होगा। उन्होंने वन पंचायतों को और मजबूत किए जाने और जिले स्तर पर कार्बन क्रेडिट का डैशबोर्ड बनाने के लिए कहा।

एमकेएससी अल्मोड़ा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. जी सी एस नेगी ने बताया कि वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट की मांग बढ़ रही है और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों की वन पंचायतें इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। यदि स्थानीय समुदाय संगठित होकर वैज्ञानिक पद्धति से वनों का संरक्षण करते हैं तो वे कार्बन क्रेडिट अर्जित कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से आय प्राप्त कर सकते हैं।

वहां मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि प्रो. एसपी सिंह, विशिष्ट अतिथि डीएफओ सिविल सोयम, डीएफओ प्रदीप धौलाखंडी, एसएसजे विवि के कुलपति प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट, पूर्व निदेशक वन्यजीव संस्थान देहरादून मुख्य अतिथि डॉ. जीएस रावत, पद्मश्री अनूप शाह, प्रख्यात पर्यावरणविद तथा आईडी भट्ट,एमकेएससी के वैज्ञानिक प्रभारी डॉ. नवीन चंद्र जोशी , जीबी पंत संस्थान के वैज्ञानिक आशीष पांडे, स्पर्द्धा संस्था के दीप बिष्ट सहित कई लोग मौजूद रहे।

सच्चे पुरस्कार का मूल्य उस कार्य में निहित है, जो किसी व्यक्ति ने समाज और समुदाय के लिए किया है। पुरस्कार का असली उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत पहचान या नौकरी बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, यह उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए, जो समाज में सार्थक बदलाव लाने में सफल रहे हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसे पुरस्कार समाज के वास्तविक विकास और भले के लिए होना चाहिए, न कि केवल एक व्यक्तिगत सम्मान का प्रतीक।

शिक्षक सम्मान: सच्चे समर्पण की पहचान और पारदर्शिता की आवश्यकता

शिक्षक सम्मान, जो हमेशा से समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त है, आजकल कुछ बदलावों का सामना कर रहा है। शिक्षा के प्रति कुछ शिक्षकों का जूनून और उनका समर्पण वाकई शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है—ग़ैर सरकारी संगठनग़ द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने की प्रक्रिया। जहां एक ओर यह कदम सराहनीय है, वहीं दूसरी ओर इसमें पक्षपात और व्यक्तिगत पसंद-नापसंद का भी असर देखा जा रहा है। विद्यालयों या महाविद्यालयों के प्रिंसिपल द्वारा नाम लेने के दौरान अक्सर यह देखा गया है कि कुछ मेहनती शिक्षकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे उनका मनोबल गिरता है।

आजकल गैर सरकारी संगठन और अन्य संस्थाएं शिक्षक सम्मान समारोहों का आयोजन करती हैं, लेकिन इन आयोजनों में पारदर्शिता की कमी साफ तौर पर महसूस होती है। शिक्षक का चयन कई बार पक्षपात या व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर किया जाता है। यह उन शिक्षकों के लिए निराशाजनक होता है, जो वर्षों से अपनी मेहनत और समर्पण से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा दे रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता। ऐसे में उनका मनोबल प्रभावित हो सकता है, और यह उनके कार्यों की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकता है।

शिक्षक-सम्मान देने वाली संस्थाओं और सरकार को इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए। जब पुरस्कार दिए जाते हैं, तो यह जरूरी है कि प्रत्येक स्तर पर पात्रता की जांच की जाए, और यह जांच सिर्फ स्कूल या महाविद्यालय के प्रिंसिपल तक सीमित न हो। इसमें विद्यार्थियों, अभिभावकों और आसपास के निवासियों का भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि वे ही उस शिक्षक के वास्तविक प्रभाव को समझते हैं। यह परख पूरे वर्ष भर चलनी चाहिए, ताकि चयन प्रक्रिया में कोई भी भेदभाव न हो और सभी को समान अवसर मिले।

आज के समाज में पुरस्कार और सम्मान एक प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। राज्य शिक्षक पुरस्कार हो या महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, इन पुरस्कारों का चयन एक निश्चित प्रक्रिया से होता है। शिक्षक को पुरस्कार प्राप्ति के लिए स्वयं

जहां तक पुरस्कार की बात है, मैं पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का पूरी तरह सम्मान करती हूं, लेकिन मेरा मानना है कि पुरस्कार का असली उद्देश्य कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। यदि पुरस्कार के माध्यम से किसी स्कूल को बेहतर संसाधन, रास्ता, मैदान, कमरे या कोई अन्य जरूरी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो मैं हाथ जोड़कर पुरस्कार हेतु आवेदन करूंगी, ताकि स्कूल और बच्चों का भला हो सके। लेकिन मैं किसी पुरस्कार के लिए खुद को कभी आगे नहीं बढ़ाऊंगी, यदि वह पुरस्कार केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए हो।

आवेदन करना पड़ता है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन, तस्वीरें, विडियो, विभागीय आख्या, पुलिस वेरिफिकेशन और इंटरव्यू जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसके बावजूद, बहुत से पुरस्कार इस रूप में प्रचारित होते हैं जैसे यह केवल कार्य के कारण मिले हैं, जबकि असल में इसे प्राप्त करने के लिए कुछ शिक्षक अपनी व्यक्तिगत पहुंच और प्रभाव का सहारा लेते हैं।

वास्तव में, यह चयन प्रक्रिया इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि पुरस्कार के लिए योग्य शिक्षक स्वयं आगे आएं, क्योंकि पहले जब अधिकारियों द्वारा चयन किया जाता था, तो निष्पक्षता या भाई-भतीजावाद का खतरा बना रहता था। लेकिन यहीं पर एक गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। हर नियम और प्रक्रिया को बिगाड़ने वाले लोग हर क्षेत्र में होते हैं। इनकी वजह से कभी-कभी वे लोग पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं जो शायद उतने योग्य नहीं होते, बल्कि उनकी पहुंच और गलत तरीके से पुरस्कार प्राप्त करने की कला उन्हें सफल बना देती है। यही कारण है कि अच्छे शिक्षक भी कभी-कभी आलोचना का शिकार हो जाते हैं।

यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या सच में हमें पुरस्कार के लिए आवेदन करना चाहिए? मेरी विचारधारा से यह मेल नहीं खाता कि मैं स्वयं पुरस्कार मांगूं। पुरस्कार प्राप्त करना एक सम्मान की बात है, लेकिन क्या उसे प्राप्त करने के लिए स्वयं आगे आना सही है? एक शिक्षक का असली उद्देश्य अपनी शिक्षा और छात्रों के विकास में योगदान करना होता है, न कि अपनी नौकरी या वेतन बढ़ाने के लिए पुरस्कार प्राप्त करना।

जब हम पुरस्कारों को केवल व्यक्तिगत फायदे के रूप में देखते हैं, तो यह सवाल उठता है कि इस पुरस्कार से स्कूल, बच्चों, समाज और समुदाय को क्या फायदा होता है? क्या इसका कोई वास्तविक प्रभाव समाज में दिखता है, या यह सिर्फ एक सम्मान और पहचान का प्रतीक बनकर रह जाता है? अक्सर हम यह नहीं देख पाते कि पुरस्कार मिलने से स्कूल के बुनियादी ढांचे, विद्यार्थियों की शिक्षा, या समग्र समाज के भले के लिए कुछ ठोस बदलाव आया हो।

जहां तक पुरस्कार की बात है, मैं पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का पूरी तरह सम्मान करती हूं, लेकिन मेरा मानना है कि पुरस्कार का असली उद्देश्य कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। यदि पुरस्कार के माध्यम से किसी स्कूल को बेहतर संसाधन, रास्ता, मैदान, कमरे या कोई अन्य जरूरी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो मैं हाथ जोड़कर पुरस्कार हेतु आवेदन करूंगी, ताकि स्कूल और बच्चों का भला हो सके। लेकिन मैं किसी पुरस्कार के लिए खुद को कभी आगे नहीं बढ़ाऊंगी, यदि वह पुरस्कार केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए हो।

सच्चे पुरस्कार का मूल्य उस कार्य में निहित है, जो किसी व्यक्ति ने समाज और समुदाय के लिए किया है। पुरस्कार का असली उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत पहचान या नौकरी बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, यह उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए, जो समाज में सार्थक बदलाव लाने में सफल रहे हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसे पुरस्कार समाज के वास्तविक विकास और भले के लिए होना चाहिए, न कि केवल एक व्यक्तिगत सम्मान का प्रतीक।

-प्रियंका सौरभ

हिंदी का गुणगान करो

भारत की भाषा हिंदी है
हिंदी का तुम मान करो
क्यों पड़े हो अंग्रेजी के पीछे
तुम हिंदी का गुणगान करो
जिस देश का नाम ही हिंदी हो
जिसके माथे की बिंदी हो
उस देश में हिंदी क्यों पीछे
जरा इसका तुम ध्यान करो
तुम हिंदी का गुणगान करो
जब बाहर कभी हम जाते है
अपने को हिन्दोस्तानी बताते हैं
वह अपनी मातृ भाषा बोलते हैं
हम अंग्रेजी में बतियाते हैं
पैदा हम हिंदी में हुए
हिंदी में ही मर जायेंगे
हिंदी तो माता है अपनी
नहीं इसको भूल पाएंगे
क्यों विमुख हो रहे हिंदी से
हिंदी भाषा तुम अपनाओ
मां है हिंदी जान है हिंदी
बोलते इसको मत शरमाओ
जितना मर्जी कोई जोर लगा ले
नहीं होगा इसका रुतबा कम
हिंदी का रास्ता जो रोक सके
नहीं किसी में इतना दम
हिंदी हिन्द की पहचान है
कौन आज इससे अनजान है
हिन्द की रग रग में बसी है हिंदी
हिंदी उगते सूरज के समान है
जब कोरोना सब पर भारी था
तब दूरी सब अपनाते थे
पास आने से डरते थे
नमस्ते से काम चलाते थे
नमस्ते ने ही पूरे विश्व को
एक नया संदेश दिया
भारतबासी हैं सबसे आगे
दुनियां को यह बता दिया

घुमारवीं
जिला बिलासपुर
हि प्र

हिंदी दिवस का संदेश: मातृभाषा में शिक्षा ही वास्तविक प्रगति

भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, संस्कृति और समाज से जुड़ने का आधार है। जिस भाषा में हम सोचते, सपने देखते और अभिव्यक्त होते हैं, वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में मातृभाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता और गर्व का भाव पैदा करना है। हिंदी दिवस केवल हिंदी के प्रचार-प्रसार का अवसर नहीं है, बल्कि यह मातृभाषाओं के महत्व और शिक्षा में उनके उपयोग पर विचार करने का भी अवसर है।

मातृभाषा व्यक्ति की सोच, संस्कार और भावनाओं से गहराई से जुड़ी होती है। यह बच्चों के लिए सीखने का सबसे स्वाभाविक और सहज माध्यम है। जब कोई बच्चा अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करता है तो वह अधिक आत्मविश्वास और रुचि से सीखता है। मातृभाषा बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता को विकसित करती है, यह उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ती है, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाला छात्र बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाता है और यह शिक्षा को रटने की बजाय समझने की प्रक्रिया बनाती है।

भारत सरकार ने 34 वर्षों बाद 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। इस नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने का मार्ग प्रशस्त किया। सबसे अहम निर्णय था कि कक्षा 5 तक और जहां संभव हो वहां 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा उसी भाषा में मिलेगी जिसमें वे घर और समाज में बातचीत करते हैं। अनुसंधानों से भी यह सिद्ध हुआ है कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा मिलने से बच्चे की समझ बेहतर होती है, ड्रॉपआउट दर कम होती है और कक्षा में उनकी भागीदारी अधिक होती है। भारतीय संविधान भी मातृभाषा में शिक्षा का समर्थन करता है। अनुच्छेद 350अ कहता है कि राज्यों को भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। कोठारी आयोग (1964-66) ने सुझाव दिया था कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा स्थानीय जनजातीय भाषा में होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) में भी यह प्रावधान किया गया कि जहां तक संभव हो, शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा हो।

आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभिभावक अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में माता-पिता बच्चों

मातृभाषा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कृति से जुड़ाव का माध्यम है। नई शिक्षा नीति (2020) ने कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया है, जिससे बच्चों की समझ, आत्मविश्वास और भागीदारी बढ़ेगी। अंग्रेजी का महत्व अपनी जगह है, परंतु प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही सबसे प्रभावी है। चुनौतियों के बावजूद मातृभाषा आधारित शिक्षा से ड्रॉपआउट दर घटेगी, रचनात्मकता बढ़ेगी और बच्चा अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। हिंदी दिवस हमें यही संदेश देता है कि मातृभाषा ही सच्ची शिक्षा और राष्ट्रनिर्माण का आधार है।

को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजने की होड़ में लगे रहते हैं। वे मानते हैं कि अंग्रेजी ही सफलता की कुंजी है। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना केवल ₹अंग्रेजीह को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रामीण भारत में निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में दाखिले की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि भाषा कभी भी सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। असली सफलता अच्छी शिक्षा, आत्मविश्वास और ज्ञान पर आधारित होती है। यदि बच्चे को ऐसी भाषा में शिक्षा दी जाए जिसे वह समझ ही नहीं पाता, तो न तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और न ही वह शिक्षा का सही लाभ ले पाएगा।

मातृभाषा में शिक्षा देने के अनेक लाभ हैं। बच्चा उसी भाषा में आसानी से सोच सकता है जो उसकी मातृभाषा है। अपनी भाषा में सीखने से भयमुक्त वातावरण मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। मातृभाषा में शिक्षा से बच्चा अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा रहता है। जब शिक्षा सरल और बोधगम्य होगी तो बच्चे स्कूल छोड़ेंगे नहीं। मातृभाषा में सोचने और व्यक्त करने से सृजनात्मक क्षमता भी विकसित होती है।

लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने में कई व्यावहारिक समस्याएँ सामने आती हैं। भारत में भाषाओं और बोलियों की बहुत अधिक विविधता है। कई भाषाओं के पास मानकीकृत लिपि या पर्याप्त शिक्षण सामग्री नहीं है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, जो बहुभाषी कक्षाओं को संभाल सकें। नई पुस्तकों और प्रशिक्षण पर अतिरिक्त खर्च आएगा। साथ ही, अभिभावकों की मानसिकता भी एक बड़ी चुनौती है जो अंग्रेजी को ही श्रेष्ठ मानती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। बहुभाषी शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ। मातृभाषाओं में गुणवत्तापूर्ण किताबें तैयार की जाएँ। अभिभावकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएँ ताकि वे समझें कि मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के लिए अधिक लाभकारी है। विभिन्न राज्यों में मातृभाषा आधारित शिक्षा के प्रयोग किए जाएँ और उनकी सफलता के आधार पर आगे बढ़ा जाए। डिजिटल शिक्षा सामग्री को भी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए।

दुनिया के कई देशों में मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली विश्व में सर्वोत्तम मानी जाती है और वहां प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पर ही जोर दिया जाता है। जापान और दक्षिण कोरिया ने अपनी भाषा में शिक्षा देकर विश्व स्तर पर आर्थिक और तकनीकी प्रगति हासिल की। यूनैस्को भी लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए।

हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि अपनी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान का आधार है। यदि हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी आत्मविश्वासी, ज्ञानवान और रचनात्मक बने तो हमें शिक्षा में मातृभाषा का स्थान सुनिश्चित करना होगा। हिंदी सहित सभी मातृभाषाओं का सम्मान करना आवश्यक है। मातृभाषा में शिक्षा देने का विचार कोई नया नहीं है, लेकिन इसे व्यावहारिक रूप से लागू करने की जरूरत है। अंग्रेजी का महत्व अपनी जगह है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही सबसे प्रभावी सिद्ध हो सकती है। हमें यह धारणा तोड़नी होगी कि केवल अंग्रेजी माध्यम से ही सफलता मिलती है। सफलता का असली आधार है— ज्ञान, समझ और आत्मविश्वास। इस हिंदी दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी भाषा और संस्कृति के महत्व को पहचानेंगे, अभिभावकों को जागरूक करेंगे और बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यही वास्तविक राष्ट्र निर्माण की दिशा में हमारा योगदान होगा।

डॉ. सत्यवान सौरभ,

वोट चोर-गद्दी छोड़ की जुगाली करते देश के पालतू मवेशी

जी हां ! प्रस्तुत व्यंग्य शुद्ध मवेशी संस्कृति को इंगित करता एक आंखे खोलने वाला आलेख है जिसे पढ़कर कुछ ठौर और धिंढोर के आंखो में सूजन आ सकती है । कल किसी दिशा से आवाज आई- ' वोट चोर, गद्दी छोड़। वोट चोर ने इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया क्युकी वोट चोर उसी की पार्टी का पुराना बूथ लुटेरा था जो मतपत्र की पेटिया लूट लिया करता था । फिर दो दिशाओं से आवाज आई तो भी उसने यही किया । जब तीन दिशाओं से आवाज आने लगी तो उसने दोनों कानों में रुई ठूंस ली और खुद जोर - जोर से वही चिल्लाने लगा । मगर जब चारों दिशाओं से यही आवाज आने लगी तो वह कुछ- कुछ घबराया, कुछ- कुछ चौंका ! कहीं पब्लिक सब समझ तो नहीं गई ! मैं तो खुद ही पुराना चोर हूं ? फिर भी उसने कहा कि अच्छा जी, मेरे रहते ऐसा हो गया है। वोटों की चोरी हो गई है ! मुझे तो पता ही नहीं चला। बेटा नवरतन चल तोतली आवाज में सुना भोट चोर अब्सिडी छोड़ ! नवरतन भौचक्का ! नेता जी को आज क्या हुआ खुद को ही तोर कहलवा रहे । मुझे पहले पता चल जाता तो मैं तुरंत रोक देता । मैं घनघोर लोकतांत्रिक मानवी हूं। मुझे पद का शौक नहीं। हार जाता तो पियरका चाच्चा को उठाकर चल देता । अब मैं असली चोर का पता लगाऊंगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। इसके बावजूद आपको शक है कि भैया ही भोट चोर है तो बता दू भैया जी के पापा जी भोट नहीं मतपेटिका चोर थे , भैया जी तो टोटी चोर है । तो इस तथाकथित चोरी के पाप के प्रक्षालन के लिए मैं आज ही अपने सिर पर उस्तरा चलवाने को तैयार हूं मगर तब आपको भईया जी को टोटी चोर कहना बंद करना होगा ! केश त्याग का हिन्दू धर्म में बहुत महत्व है ! मगर 'वोट चोर गद्दी छोड़' की आवाज थमेगी नहीं। लोगों ने कहा, हमें तुम्हारे सिर के बालों से कोई मतलब नहीं। वैसे भी तुम गंजे हो। त्यागने के लिए तुम्हारे पास कुल चार ही तो लंबी नाक हैं। फिर भी बाल तो तुम जितने चाहे, उगा लो। पूरी खोपड़ी बालों से भर लो मगर हो तो तुम मतपेटिका चोर के बेटे थे हो और रहोगे। तभी बिहार से कोई बोला 'वोट चोर गद्दी छोड़'। तेजपत्ता दास ने स्लोगन लपक लिया और कहा -' गद्दी और मैं और गद्दी छोड़ दूं ? यह हो नहीं सकता ! पापा की गद्दी कोई छोड़ता है भला ? गद्दी छोड़ने के लिए होती है !मैं जीवन छोड़ सकता हूं, गद्दी नहीं !चलो फिर भी तुम्हारा मन रखने के लिए मैं अपनी बरसों से प्यार से पाली हुई दाढ़ी छोड़ सकता हूं, जिसमें एक भी तिनका नहीं है। फिर तो मैं चोर लगूंगा भी नहीं। बिहार के लोगों ने कहा, हमें तेरी दाढ़ी से कोई मतलब नहीं। तू चाहे तो गुरुदेव जैसी दाढ़ी रख ले। चंद्रशेखर रावन जैसी मूंछें उगा ले। चोर तो फिर भी चोर ही रहेगा। 'वोट चोर गद्दी छोड़'। तभी मुंबई में खाकरे परिवार का बन्दा बोला ! अच्छा ऐसा है कि आजकल के चोर डकैत ऐनक पहनने लगे हैं। मैं भी ऐनक पहनता हूं । चलो, मैं इस महंगी ऐनक का त्याग करने के लिए तैयार हूं। गद्दी बचाने के लिए कोई भी त्याग छोटा नहीं। वैसे भी मुझे पढ़ने- लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं ! पढ़ने- लिखने वालों को मैं अपना दुश्मन मानता हूं। फिर आवाज आई, तू ऐनक तो बच्चों की तरह एक के ऊपर चाहे चार और पहन ले या दस- बीस पहन ले। देशी पहन ले या विदेशी पहन ले। एक लाख की पहन ले या दस लाख की पहन ले या मत पहन मगर ' वोट चोर, गद्दी छोड़'। तभी बंगाल से कोई दीदी टाईप की उड़ेल बोल पड़ी अच्छा चलो, 'मैं चप्पल पहनना छोड़ दूंगी । बुर्का पहनने लगूंगी ।अब तो खुश। अब तो नहीं कहोगे, वोट चोर....' जनता ने कहा, तू जूते पहन या चप्पल पहन या चाहे नंगे पांव रह।'वोट चोर, गद्दी छोड़।' तभी कर्नाटक से किसी ने कहा, अच्छा चलो, बंडी पहनना छोड़ सकता हूं। उससे भी जब बात नहीं बनी तो उसने कुर्ता उतारने का प्रस्ताव दिया। फिर उसने कहा कि बनियान भी उतार दूंगा ।उसने कहा, मैं कुर्सी के लिए तो पजामा भी उतार सकता हूं बस अपने गान्दी सर कह दे ! मगर इसके अंदर अंडरवियर नहीं है। फिर भी चलो, कुछ करके दिखाता हूं। तब भी चारों ओर से एक ही आवाज आ रही थी- 'वोट चोर गद्दी छोड़'। चोर वोटर अधिकार यात्रा की वैन के अंदर गया। पजामा छोड़कर चड्डी पहनकर आया। आवाज आई।अरे बेशर्म चोर, कपड़े पहन, बिहार छोड़। बेशर्म चड्डी में गद्दी पर बैठना चाह रहा। नीचे से आवाज आई - चमचों का राजा नंगा है। राजा ने कहा, नहीं, राजा हरी चड्डी में है। नीचे से फिर कुछ लोगो की आवाज आई -' वोट चोर, गद्दी छोड़। अगली बार जब आवाज आई - 'वोट चोर' तो चोर ने भी नारे में जवाब दिया - 'गद्दी छोड़ '। अगली बार खुद चोर ने नारा लगाया - 'वोट चोर' नीचे से आवाज आई -' गद्दी छोड़ ।' कभी भाड़े की जनता कहती 'वोट चोर', तो चोर कहता,' गद्दी छोड़'। कभी चोर कहता, 'वोट चोर ' तो जनता कहती- 'गद्दी छोड़'। और इस तरह चोर यह खेल जनता से खेलता रहा और जब वह समझ गया कि उसके इस खेल को भी जनता समझ गई है इतना सुनते ही मै वहां से अंतर्ध्यान हो गया।

इंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर यूपी

घूँघट की बगावत

14 सितम्बर 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

भाइयों आदमी को जिंदगी में आड़े तिरछे काम नहीं करना चाहिए क्या ये जिंदगी में कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। जावेद खां ये नाम सुनते ही शायद आपका ध्यान न जाए पर जैसे ही उनका चेहरा आपकी नजरों के सामने आता है आपको अंदाज अपरा अपना का वह लेखक याद आ जाता है। या लगान में गांव वाले के लिए हर एक बॉल पर कमेंट्री करने वाला इंसान` पर्दे पर उनकी भूमिकाएं भले ही छोटी रहीं पर उनका अभिनय हम सब के जेहन में हमेशा के लिए बस गया। यहां पर हम जावेद खां अमरोही की चर्चा करेंगे। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसके सपने किसी और मैदान पर लिखे गए थे। पर किस्मत ने एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पहुंचा दिया।

फिल्म जगत के अनमोल रत्न : जावेद खां अमरोही

24 मार्च 1949 को मुंबई में पेशे से चिकित्सक के घर में जन्में जावेद खान के दिल में न तो डॉक्टर बनने की चाह थी और न ही किसी और पेश की। उनके दिल में अगर कुछ था तो वह था सिर्फ क्रिकेट। बचपन से ही बल्ले और बॉल के साथ उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनका पूरा बचपन इसी जुनून में गुजरा' मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के 36 सुविधा खिलाड़ियों की सूची में उनका नाम भी शामिल था। उन्हें लगा था कि मुंबई के खालसा कॉलेज में दाखिला मिल जाए तो क्रिकेटर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। पर जिंदगी का खेल तो कुछ और ही था। उनके पिता के देहांत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। किस्मत अच्छी थी खालसा कालेज ने उन्हें फ्री एडमिशन और स्कॉलरशिप देवी लेकिन उनका क्रिकेट करियर 253 होते हो वाला था तभी एक बीमारी ने उन्हें घेर लिया। किडनी की तकलीफ ने न सिर्फ उनका क्रिकेटर बनने का सपना छीन लिया बल्कि कॉलेज की स्कॉलरशिप भी रुकवा दी। अब उन्हें डर था कि पढ़ाई रुक जाएगी। तभी उनकी मुलाकात कॉलेज के ड्रामा हेड रमेश तलवार से हुई। रमेश तलवार को उनकी उर्दू शैली बहुत पसंद आई और उन्होंने उनसे वादा किया कि अगर वे उनके नाटक में काम करने को तैयार हो जाएं तो वे उनकी रुकी हुई स्कॉलर शिप दोबारा शुरू करवा देंगे। जावेद खां को ये ऑफर बहुत पसंद आया। पर अभिनय के चक्कर वे इतने व्यस्त हो गए कि क्रिकेटर बनने की इच्छा समाप्त हो गई और वे पढ़ाई में भी पीछे रहने लग गए। स्कॉलरशिप के लिए शुरू हुआ ये सफर इतना आगे बढ़ा कि उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के ड्रामा एसोसिएशन के चेयर मैन का पद संभाला फिर किरन कुमार जैसे कलाकारों के कहने पर वे सीधे पुणे के एफटीआईआई में दाखिल हो गए। जहां उन्हें अभिनय की वास्तविक गहराई का पता चला। एफटीआईआई में उनकी मुलाकात नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे कलाकारों से हुई जिसके साथ उनकी दोस्ती सालों तक कायम रही। उनका मारना था कि एफटीआईआई ने उन्हें ने सिर्फ अभिनय नहीं सिखाया बल्कि जिंदगी जीने का सलीका भी सिखाया।

फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले जावेद खान ने थिएटर में बहुत काय किया था। उनके सहपाठी और दोस्त बताते हैं कि वे मंच पर इतनी ऊर्जा और विश्वसनीयता से काम करते थे कि दर्शक उन्हें देखते ही रह जाते थे। उनकी उर्दू जबान पर उनकी पकड़ और संवादों को कहने का उनका अनोखा अंदाज उन्हें बाकी कलाकारों से उन्हें अलग करता था। थिएटर में काम करने के दौरान ही उन्हें पता चला कि उनकी प्रतिभा सिर्फ गंभीर किरदारों के लिए ही नही बल्कि हास्य भूमिकाओं भी कमाल कर सकते हैं। एफटीआईआई में दाखिल होने से पहले ही वे कुछ फिल्मों में दिख चुके थे। जैसे- जंजीर, जलते बदन और दूसरा आदमी इन फिल्मों में उनकी छोटी छोटी भूमिकाएं थीं जिनमें वे चंद सेकेंड के लिए पर्दे पर आते थे। पर उनका चेहरा दर्शकों के जेहन में जरूर रह जाता । फिल्म इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद उन्हें बड़ी भूमिकाएं मिलने लगी। पूरी फिल्म में एक खलनायक के रूप में उन्हें अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला। इस फिल्म में उनका किरदार भले ही छोटा था। पर उन्होंने इसे इतनी शिद्दत से निभाया कि उनकी पहचान खलनायक के रूप में भी बन गई। जावेद खान ने पूरे कैरियर में सैकड़ों फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम किया। उनकी अदाकारी इतनी सहज थी कि वे हर किरदार में' जान डाल देते थे। 90 के दशक में आई कॉमिक फिल्म अंदाज अपना-अपना में वह लेखक आनंद अकेला का किरदार निभाते हैं। फिल्म के मुख्य किरदार सलमान खां और आमिर खान के साथ उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि उनके छोटे-छोटे सीन भी बहुत यादगार बन गये। जावेद खान ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि टेलीविजन में भी खूब नाम कमाया। 80 के दशक के टेली धारावाहिक- नुक्कड़ में उनका किरदार एक ऐसा किरदार था जो आज भी लोगों को याद है। ये धारावाहिक तत्कालीन समाज की वास्तविकताओं से लोगों को परिचित कराता था। इस के अलावा उन्होंने घर जमाई और मिर्जा गालिब जैसे धारावाहिकों में भी काम किया। उनकी आवाज ...और लहजा लोगों के दिलों में उतर जाता था।

पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता : चेंजिंग द नैरेटिव आन सुसाइड विषय पर विद्यार्थियों ने उकेरा अपनी अभिव्यक्ति

कुशीनगर। बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में मनोविज्ञान विभाग की तरफ से गत दिनों बुधवार को पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें स्नातक, परास्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनका हौंसला बढ़ाया गया। कॉलेज में आयोजित पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में चेंजिंग द नैरेटिव आन सुसाइड विषय पर विद्यार्थियों ने पोस्टर मेकिंग कर अपनी अभिव्यक्ति को उकेरा। प्रतियोगिता में अंजली कुशवाहा प्रथम, मुनज्जह समीम खान द्वितीय व शशि सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा अंशिका राव, मानसी सिंह, आलिया खान, निधि पांडेय, श्रेया त्रिपाठी , शालू मद्धेशिया को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर उर्मिला यादव ने कहा कहा कि आधुनिक दौर में मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का बहुत ही गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे आत्महत्या की भावना हर आयु वर्ग में देखी जा सकती है। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर विनोद मोहन मिश्र ने किया। अंत में प्रोफेसर सीमा त्रिपाठी ने सभी अतिथियों के प्रति आभार जताया। इस दौरान अमरेंद्र कुमार तिवारी, शमसुद्दीन अंसारी, शैलेश साहनी, प्रोफेसर राम भूषण मिश्रा आदि मौजूद रहे।

फर्जी खबरें सार्वजनिक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा

कौन सहमत नहीं होगा कि फर्जी खबरों पर रोक के लिए कड़े.दंड़ात्मक प्रावधान होने चाहिए। चिंता कितनी बढ़ गई है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि फर्जी खबरों पर विचार के लिए संसदीय समिति का गठन करना पड़ा। इसी क्रम में एक संसदीय समिति ने फर्जी खबरों को सार्वजनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा बताते हुए इस चुनौती से निपटने के लिए दंड़ात्मक प्रावधानों में संशोधन, जुर्माना बढ़ाए जाने और जवाबदेही तय किये जाने की मांग की गई है। अपनी मसौदा रिपोर्ट में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने प्रिंट, ड़िजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीड़िया संस्थानों में तथ्य-जांच तंत्र और आंतरिक लोकपाल की अनिवार्य उपस्थिति की भी जरूरत बताई। यह तो नई बात हो गई। तथ्य जांच के लिए अलग से तंत्र बनाना पड़े। तो किसी भी संस्थान के संपादकीयकर्मी क्या करेंगे और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार लोगों का काम क्या बिना सत्यता की जांच किए खबरें जुटाना होगा जिन्हें संपादकीयकर्मी बिना जांचे-परखे तथ्य जांच तंत्र के हवाले कर देंगे। तो फिर सूचनाओं के प्रकाशन और प्रसारण की इन महत्वपूर्ण कड़ियों से बनी पूरी व्यवस्था ही हिल जाएगी।

> दरअसल, सारी खबरों की व्यवस्थाएं सोशल मीड़िया और ड़िजिटल पत्रकारिता' की उस जमात के पैदा हो जाने के बाद बिगड़ी हैं, जिसकी कोई जिम्मेदारी ही तय नहीं की गई है। वे कथित पत्रकार जो मर्जी में आए वो कहते फिरते हैं।

दरअसल, सारी खबरों की व्यवस्थाएं सोशल मीड़िया और ड़िजिटल पत्रकारिता' की उस जमात के पैदा हो जाने के बाद बिगड़ी हैं, जिसकी कोई जिम्मेदारी ही तय नहीं की गई है। वे कथित पत्रकार जो मर्जी में आए वो कहते फिरते हैं। लाइक और फॉलोअर बढ़ाने के मोह में पड़े टीवी न्यूज चैनल भी इनके फेर में आ गए हैं, तुरंत लगाम इस तालमेल पर लगनी चाहिए। इस भेड़-चाल में कुछ हद तक प्रिंट मीड़िया भी आ गया है। जहां तक आंतरिक लोकपाल की बात है उसे स्वीकार किया जा सकता है। मसौदा रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी उल्लेख है क्योंकि समिति इस मंत्रालय की भी पड़ताल करती है। लगता है कि अब मीड़िया संस्थानों के मालिकों और प्रकाशकों को भी जिम्मेदार ठहराने पर विचार किया जा रहा है। फर्जी खबरें फैलाने के लिए बिचौलियों और मंचों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत बताते हुए समिति ने प्रकाशन और प्रसारण पर नकेल कसने के लिए मौजूदा अधिनियमों और नियमों में दंड़ात्मक प्रावधानों में संशोधन की जरूरत पर बल दिया है। मीड़ियाकर्मियों को सावधान और जिम्मेदार हो जाना चाहिए।

फिल्म मन्नू क्या करेगा : भावनात्मक, प्रेरणादायक और बेहद व्यक्तिगत

मुंबई। आज कल दर्शक केवल मसालेदार एंटरटेनमेंट के पीछे नहीं भागते। कभी-कभी एक सीधी-सच्ची कहानी, बिना किसी तड़क-भड़क के, बिना किसी आइटम नंबर के ऑडियंस के दिल में घर कर लेती है। ह्यमन्नू क्या करेगाह्न उन्हीं फिल्मों में से एक है – जो चुपचाप आती है, धीरे-धीरे दिल में उतरती है और फिर वहां एक कोना हमेशा के लिए घेर लेती है।

ये कोई फिल्मी फिल्म नहीं है। इसमें न कोई सुपरहीरो है, न बड़ा विलेन। ये कहानी है हम जैसे, आप जैसे किसी आम इंसान की जिसकी ज़िंदगी में सवाल तो बहुत हैं, पर जवाब धीरे-धीरे, अपने समय पर आते हैं। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है।

देहरादून में बसी ये कहानी है मानव चतुर्वेदी उर्फ मन्नू (व्योम यादव) की – एक ऐसा लड़का जो बाहर से बेफिक्र, खुशमिजाज और दोस्ताना है, लेकिन अंदर से बेहद उलझा हुआ। कॉलेज में लोकप्रिय, हँसमुख और हमेशा दूसरों की मदद को तैयार मन्नू की सबसे बड़ी दिक्कत है – वो नहीं जानता कि उसे ज़िंदगी से चाहिए क्या। फिर उसकी मुलाकात होती है जिया (साची बिंद्रा) से – जो खुद में आत्मनिर्भर, बेबाक और ज़िंदगी से भरी हुई है। दोनों की दोस्ती, फिर मोहब्बत, और उससे भी बढ़कर – मन्नू की अपनी पहचान की तलाश – यही फिल्म की आत्मा है।

संजय त्रिपाठी का निर्देशन बहुत ही संतुलित और ईमानदार है। उन्होंने कहानी को बहुत संभलकर, बिना

किसी ओवरडोज इमोशन या नाटकीयता के पेश किया है।कई दृश्य ऐसे हैं जो संवादों के बिना भी बहुत कुछ कह जाते हैं। खासतौर पर मन्नू की चुप्पियाँ, उसकी सोचती हुई आंखें–दर्शकों को अंदर तक छू जाती हैं।

व्योम यादव एक बेहद सहज अभिनेता हैं। डेब्यू फिल्म में उन्होंने जिस परिपक्वता से मन्नू का किरदार निभाया है, वो काबिल-ए-तारीफ है। उनकी मासूमियत, उलझन और आत्मिक परिवर्तन को उन्होंने बेहद सच्चाई से जिया है। वह इंडस्ट्री में जल्द ही अपनी अलग पहचान बना लेंगे। साची बिंद्रा ने जिया के किरदार को ताजगी और आत्मबल के साथ निभाया है। वो सिर्फ ह्यनायिकाह्न नहीं हैं – जिया मन्नू के जीवन की राहों की रोशनी बन जाती है। दोनों की केमिस्ट्री ऑडियंस को खूब पसंद आएगी। विनय पाठक, कुमुद मिश्रा, राजेश कुमार, चारु शंकर, और बृजेंद्र काला जैसे मंजे हुए कलाकारों ने भी अपने हिस्से को खूबसूरती से निभाया है। खासकर विनय पाठक का किरदार फिल्म में हल्केपन के साथ एक गहरी बात कह जाता है।

फिल्म का संगीत इसकी आत्मा है। नौ गानों की एल्बम में कोई भी गाना 'फिलर' नहीं लगता – हर गाना कहानी के किसी न किसी मोड़ पर भावनाओं को और गहराई देता है।मन्नू तेरा क्या होगाह्न फिल्म की थीम को हल्के-फुल्के अंदाज में बयान करता है। हमनवा, फना हुआ, और तेरी यादें दिल को छूने वाले गीत हैं, जो लंबे समय तक जेहन में रह जाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी हर सीन को सपोर्ट करता है–ना ज्यादा, ना कम – एकदम सटीक।

देहरादून की वादियाँ, पहाड़ियों का शांत वातावरण और छोटे शहर की मिठास – फिल्म का सिनेमैटोग्राफी बहुत खूबसूरत है। एडिटिंग भी फिल्म की गति को सहज बनाए रखती है। कहीं कोई दृश्य खिंचा हुआ नहीं लगता, और न ही कुछ अधूरा।सौरभ गुप्ता और राधिका मल्होत्रा की लिखी स्क्रिप्ट बहुत ही सच्चाई से भरपूर है। डायलाग ऐसे हैं जैसे आप रोज मर्रा की जिन्दगी में बोलते हो । क्यूरियस ऑय फिल्म्स द्वारा निर्मित ह्मन्नू क्या करेगाह्न एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है – कि क्या हम सब कभी ना कभी मन्नू की तरह उलझे नहीं रहते ?यह फिल्म एक अनुभव है भावनात्मक, प्रेरणादायक और बेहद व्यक्तिगत।

वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन: एक ऐतिहासिक कदम

केरल सरकार ने बुजुर्ग आबादी के सम्मान और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और केरल का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग' का गठन किया है। बता दें कि यह आयोग न केवल बुजुर्गों की मूलभूत समस्याओं जैसे कि उपेक्षा, शोषण, अकेलापन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने की दिशा में काम करेगा, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी उपलब्ध कराएगा।

आयोग वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव, ज्ञान और विचारों से समाज को लाभान्वित करने का प्रयास करेगा तथा नई पीढ़ी को समाज निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रेरणा देगा। इस प्रकार आयोग बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा का प्रहरी बनेगा। दरअसल, केरल उन राज्यों में शुमार है जहां वृद्धजन आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है।

अनुमान है कि 2026 तक राज्य की लगभग एक-तिहाई आबादी 60 वर्ष से अधिक आयु की होगी। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन न केवल समयानुकूल, बल्कि दूरदर्शी कदम भी है। जिस प्रकार केरल ने बुजुर्गों के कल्याण के लिए ठोस और संस्थागत प्रयास किए हैं, वैसे ही प्रयास पूरे देश में होने चाहिए। गौरतलब है कि भारत जैसे विशाल देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 10.38 करोड़ थी, जो कुल आबादी का लगभग 8.6 प्रतिशत हिस्सा थी। यह संख्या 2021 तक बढ़ कर 13.8 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों की मानें तो 2050 तक भारत में तीस करोड़ से अधिक बुजुर्ग होंगे और यह संख्या विश्व की सबसे बड़ी वृद्ध आबादी होगी। अनुमान है कि 2026 तक हर पांच में से एक भारतीय वरिष्ठ नागरिक होगा। यह स्थिति केवल जनसंख्या के लिहाज से नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महम्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और प्रगति का स्तर इस बात से आंका जा सकता है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अतः यह समय है कि भारत के हर राज्य में वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया जाए ताकि समाज का यह महत्पूर्ण वर्ग सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके।

बैटल ऑफ गलवान से सामने आया सलमान खान का फर्स्ट लुक

मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान से पहला ऑफिशियल लुक इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया है। शूटिंग शुरू होते ही सामने आई इस तस्वीर में सलमान आर्मी की यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। सलमान अपने इस लुक में राजसी ठाठ-बाट घनी मूंछें और तीखी नजरों के साथ देशभक्ति में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई भयानक लड़ाई के समय में फिर से लेकर जाती है। उस समय सीमा पर हुआ यह एक दुर्लभ संघर्ष था जिसमें सैनिकों ने बिना किसी हथियार के लड़ाई लड़ते हुए जान गंवाई थी। सैनिकों ने लाठी और पत्थरों से आमने- सामने की लड़ाई लड़ी थी जिससे यह हाल के भारतीय इतिहास की सबसे ज्यादा भावनात्मक कहानियों में से एक बनकर सामने आई।

48 वर्ष के हुए अक्षय कुमार

नयी दिल्ली । अभिनेता अक्षय कुमार ने मंगलवार को अपने ५८वें जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीड़िया पर एक संदेश के माध्यम से पिछले तीन दशकों में उन्हें समर्थन देने के लिए प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया।

बगावत जेन-जी की : नई पीढ़ी निरंकुशता मौन होकर नहीं बर्दाश्त कर सकती

नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीड़िया पर प्रतिबंध और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों की मौत होने के बाद स्थिति काबू से बाहर हो गई है। पुलिस के साथ हुई झड़पों में खुद को जेनझजी यानी युवा पीढ़ी बता रहे 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। काठमांडू के अलावा पूर्वी शहर इटहरी में दो लोग मारे गए। अनेक स्थलों पर कर्फ्यू, सेना सड़कों पर है। भारी झड़प व मौतों के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को राजी नहीं है। गृहमंत्री रमेश लेखक के बाद अब प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भी घटना के बाद इस्तीफा दे दिया है। सरकार की तरफ से मिले संकेतों के अनुसार जल्द ही सोशल मीड़िया से बैन हटाया जा सकता है। सरकार के रवैये और भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए संसद भवनङ्क राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, शीतल निवास पर कर्फ्यू लगा है। अभी कुछ ही महीनों पहले नेपाल में राजशाही बहाल करने को लेकर आंदोलन हो चुका है। तब भी नाराज युवाओं द्वारा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। सरकार ने पिछले सप्ताह ही फेसबुक, इंस्टाग्राम,

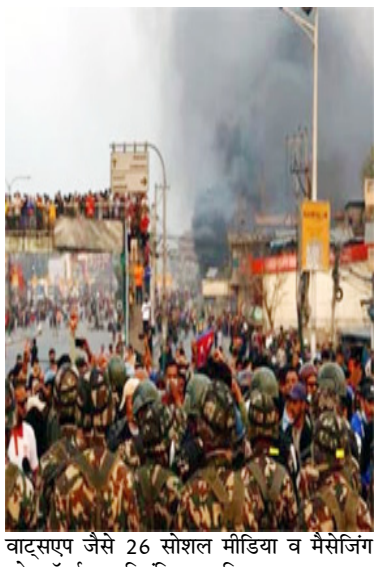

वाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया व मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंधित कर दिए गए। सरकार का आरोप है-ये सोशल मीड़िया कंपनियां कानूनों का पालन करने में कोताही कर रही हैं। चीन की सोशल मड़िया कंपनी टिकटॉक द्वारा सभी नियमों का पालन किया है इसलिए उस पर प्रतिबंध नहीं लगा है। टिकटॉक पर चल रहे नेपोबेबी ट्रेंड़ हो रहा है जिसमें नेताओं के बच्चों के ऐशो-आराम भरे जीवन की तस्वीरें व वीड़ियो वायरल किए जा रहे हैं। यह सच है कि बिलाझवजह सोशल मीड़िया को प्रतिबंधित करने से युवाओं में आक्रोश बढक्ष्स्वा स्वाभाविक है। नेपाल में भ्रष्टाचारङ्क रिश्वतखोरी व भाई-भतीजावाद को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने को पर भी नेपालियों में भारी निराशा है। वे देश की बदहाली के लिए राजनेताओं को दोषी मानते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मीड़िया वास्तविकता छिपाने में सरकार का पक्षकार बन गया है। वे इसे स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं। जनता की ताकत को नजरंदाज करने वालों को यह समझना होगा कि नई पीढ़ी निरंकुशता मौन होकर नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसे अपने अधिकारों और ताकत का अंदाजा है। नेताओं को राजशाही वाले अंदाज त्यागने होंगे।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादक: पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com